V सहकारी बैंकिंग घटनाक्रम

वर्ष 2021-22 में शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के वित्तीय प्रदर्शन में सुधार हुआ, जिसमें पूंजीगत बफ़र्स में वृद्धि, सकल अनर्जक आस्ति (जीएनपीए) अनुपात में गिरावट और बेहतर लाभप्रदता संकेतक शामिल हैं। अल्पावधि सहकारी समितियों में, राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) दोनों के तुलन-पत्रों में, पिछले वर्ष की मंदी के बाद, वर्ष 2020-21 में तेजी आई। यह उल्लेखनीय है कि डीसीसीबी की लाभप्रदता में सुधार हुआ।

1. भूमिका

V.1 सहकारी बैंक अंतिम छोर तक ऋण उपलब्ध कराने वाले मध्यस्थ के रूप में काम करते हैं और वित्तीय समावेश को बढ़ावा देते हैं। तथापि, हाल के वर्षों में इस क्षेत्र को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है जो स्वामित्व संरचना, त्रुटिपूर्ण कॉर्पोरेट अभिशासन प्रथाओं तथा जालसाजी की बढ़ती घटनाओं, साथ ही रिज़र्व बैंक एवं सरकार के दोहरे विनियमन से पैदा होने वाले मुद्दों के कारण उठ खड़ी हुई थीं। अतिरिक्त पूँजी की उगाही शेयरहोल्डिंग पैटर्नों और सांविधिक प्रावधानों के कारण बाधित होती है। कानूनी बाधाओं और अटपटे कारकों के कारण उनका त्वरित समाधान बाधित होता है।

V.2 कई वर्षों से, रिज़र्व बैंक सहकारी बैंकिंग संरचना को मजबूत करने के लिए सुधार लाने के प्रयास कर रहा है। इसकी द्विआयामी रणनीति में वैधानिक सुधार और विनियामकीय समर्थन शामिल हैं। बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 2020 में संशोधन ने शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) की पूँजी जुटाने की बाधाओं को कम कर दिया है। रिज़र्व बैंक को यूसीबी के पुनर्गठन या समामेलन का अधिकार दिया गया है। रिज़र्व बैंक ने 19 जुलाई, 2022 को यूसीबी को नियंत्रित करने वाले विनियामकीय फ्रेमवर्क को भी संशोधित किया है। इस फ्रेमवर्क का मार्गदर्शन करने वाली दृष्टि यह है कि ग्राहक आधार में विविधता को पोषित करके मित्रवत पड़ोसी बैंकों के रूप में यूसीबी की स्थिति सुदृढ़ की जाए और क्रेडिट मध्यस्थता में योगदान को बढ़ाने के लिए मजबूत यूसीबी को परिचालन में और ज्यादा लचीलापन प्रदान किया जाए।

V.3 इस पृष्ठभूमि में, यह अध्याय समीक्षाधीन अवधि के दौरान शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों के प्रदर्शन पर केंद्रित है। खंड 2 में सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की संरचना और उसके विनियमन का उल्लेख किया गया है। खंड 3 में लाभप्रदता, आस्ति गुणवत्ता और पूँजी पर्याप्तता के मामले में यूसीबी की वित्तीय व्यवहार्यता का मूल्यांकन किया गया है। खंड 4 में अल्पकालिक ग्रामीण सहकारी समितियों और दीर्घकालिक ग्रामीण सहकारी समितियों के वित्तीय प्रदर्शन की पड़ताल की गयी है। खंड 5[1] में समग्र मूल्यांकन किया गया है।

2. सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की संरचना

V.4 भारत में सहकारी बैंकिंग संरचना को वाणिज्यिक बैंकिंग संरचना के पूरक और अनुपूरक के रूप में कार्य करने के लिए विकसित किया गया था, जिसमें सीमांत उधारकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने और ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की विकास आवश्यकताओं को पूरा करने पर विशेष ध्यान दिया गया था। यूसीबी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम,

[1] हालांकि प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पीएसीएस) और दीर्घकालिक सहकारी समितियां रिज़र्व बैंक के विनियामकीय दायरे से बाहर हैं, तथापि विश्लेषण की पूर्णता के लिए डेटा और उनकी गतिविधियों का एक संक्षिप्त विवरण इस अध्याय में शामिल किया गया है।

चार्ट V.1: सहकारी बैंकों की संरचना

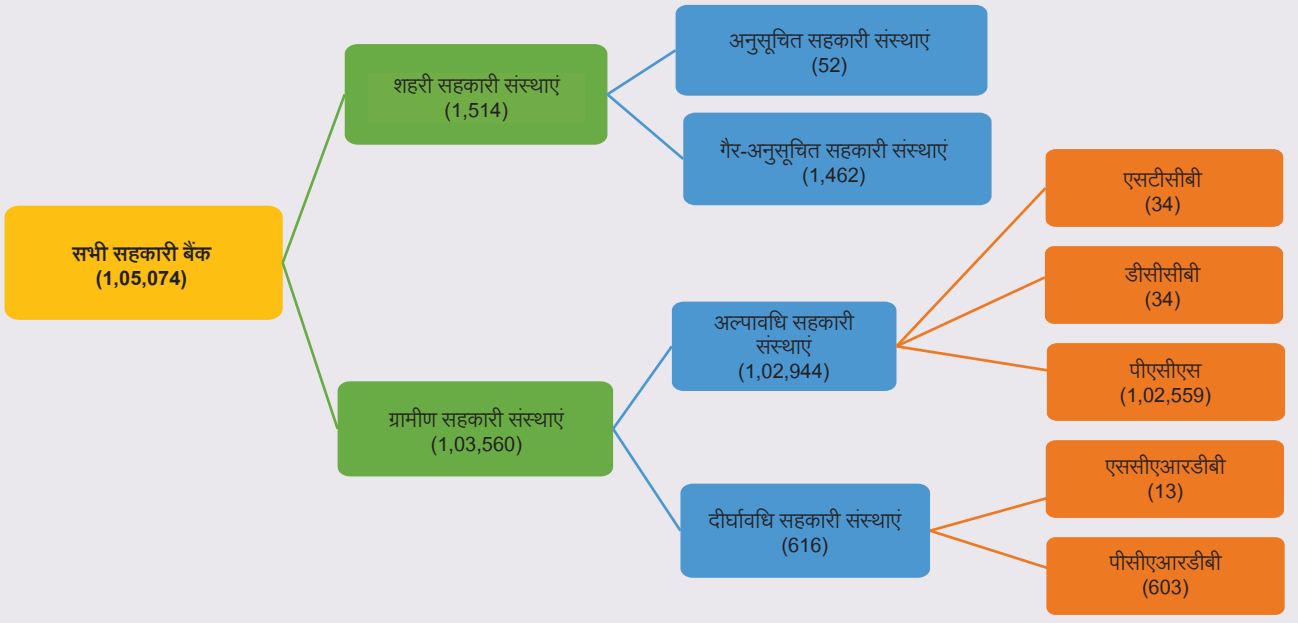

टिप्पणियां: 1. एसटीसीबी- राज्य सहकारी बैंक; डीसीसीबी: जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक; पीएसीएस प्राथमिक कृषि ऋण समितियां; एससीएआरडीबी- राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक; पीसीएआरडीबी: प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक;
2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े मार्च 2022 के अंत में यूसीबी की एवं मार्च 2021 के अंत में ग्रामीण सहकारी संस्थाओं को दर्शाते हैं।
3. तमिलनाडु औद्योगिक सहकारी बैंक लि. के अतिरिक्त डीसीसीबी।
स्रोत: आरबीआई, नाबार्ड और एनएएफएससीओबी।

1934[2] की दूसरी अनुसूची में शामिल होने या नहीं होने, और उनकी भौगोलिक पहुंच (एकल-राज्य या बहु-राज्य) के आधार पर अनुसूचित और गैर-अनुसूचित के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ग्रामीण सहकारी समितियों को उनकी गतिविधियों- अर्थात दीर्घावधि ऋण देने तथा अल्पावधि ऋण देने के आधार पर अलग किया जाता है। मार्च 2022 के अंत तक, इस क्षेत्र में 1,514 यूसीबी और 103,560 ग्रामीण सहकारी समितियाँ[3] शामिल थीं (चार्ट V.1)।

V.5 बैंकों की संख्या के साथ-साथ आस्ति-आकार के मामले में, अल्पकालिक ग्रामीण सहकारी समितियों का इस क्षेत्र पर प्रभुत्व है (चार्ट V.2)।

V.6 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी), ग्रामीण सहकारी समितियों और शहरी सहकारी समितियों के बीच

चार्ट V.2: आस्ति के आकार के अनुसार सहकारी बैंकों का विभाजन
(मार्च 2021 के अंत में)

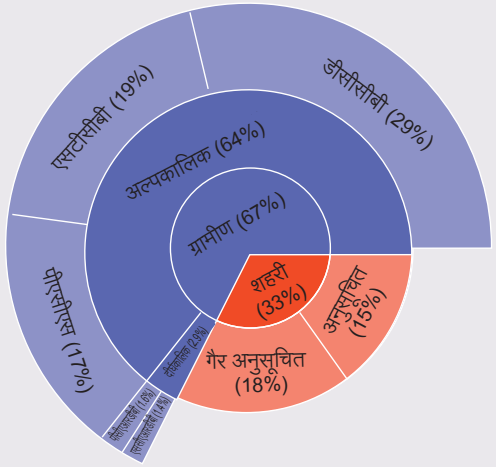

टिप्पणी: सनबर्स्ट चार्ट सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में स्तर को दर्शाता है। प्रत्येक चार्ट खंड का आकार क्षेत्र की कुल आस्तियों में इसकी हिस्सेदारी (कोष्ठक में वर्णित) के अनुपात में है।
स्रोत: आरबीआई, नाबार्ड और एनएएफएससीओबी।

[2] अनुसूचित सहकारी बैंकों के अलावा, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक भी अधिनियम की एक ही अनुसूची में शामिल हैं।

[3] ग्रामीण सहकारी समितियों के आंकड़े एक वर्ष के अंतराल के साथ उपलब्ध हैं, यानी वे वर्ष 2020-21 से संबंधित हैं।

सारणी V.1 कृषि के लिए ऋण प्रवाह में हिस्सेदारी

(प्रतिशत)

	सहकारी बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	वाणिज्यिक बैंक
1	2	3	4
2015-16	16.7	13.0	70.2
2016-17	13.4	11.6	75.0
2017-18	12.9	12.1	74.9
2018-19	12.1	11.9	76.0
2019-20	11.3	11.9	76.8
2020-21	12.1	12.1	75.8
2021-22	13.0	11.0	76.0

स्रोत: नाबार्ड के एन्श्योर पोर्टल पर बैंकों द्वारा प्रस्तुत आंकड़े।

का अंतर तेजी से समाप्त होता जा रहा है, क्योंकि ये सभी, ग्राहकों के एक ही समूह को सेवा देने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। यहां तक कि राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) जैसी अल्पकालिक ऋण सहकारी समितियां, आवास और शिक्षा के लिए दीर्घकालिक ऋण देकर अपने पोर्टफोलियो में विविधता ला रही हैं। परंपरागत ईंट-और-गारे वाले मॉडल के अलावा, एससीबी कारोबार प्रतिनिधियों पर भरोसा करते रहे हैं और अंतिम छोर तक न पहुँच पाने की समस्या को हल करने के लिए फिनटेक के लाभों का उपयोग कर रहे हैं। भीतरी इलाकों में वाणिज्यिक बैंकों की बढ़ती पैठ से सहकारी समितियों का सापेक्षिक आकार और प्रभाव कम होता जा रहा है। मार्च 2021 के अंत तक, सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के सकल तुलन पत्र का आकार ₹20 लाख करोड़ के साथ एससीबी के समेकित तुलन पत्र का 10.3 प्रतिशत था, जो मार्च 2005 के अंत में रहे 19.4 प्रतिशत से कम था।

V.7 हालांकि ग्रामीण सहकारी समितियों की स्थापना कृषि क्षेत्र को ऋण देने के उद्देश्य से की गई थी, लेकिन इस क्षेत्र को कुल ऋण देने में उनकी हिस्सेदारी वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-20 तक घटी, लेकिन उसके बाद इसमें मामूली सुधार हुआ है (सारणी V.1)।

3. शहरी सहकारी बैंक

V.8 1990 के दशक में अपनाई गई उदार लाइसेंसिंग नीति के कारण यूसीबी की संख्या में वृद्धि हुई। वर्षों से वित्तीय

चार्ट V.3: यूसीबी की संख्या

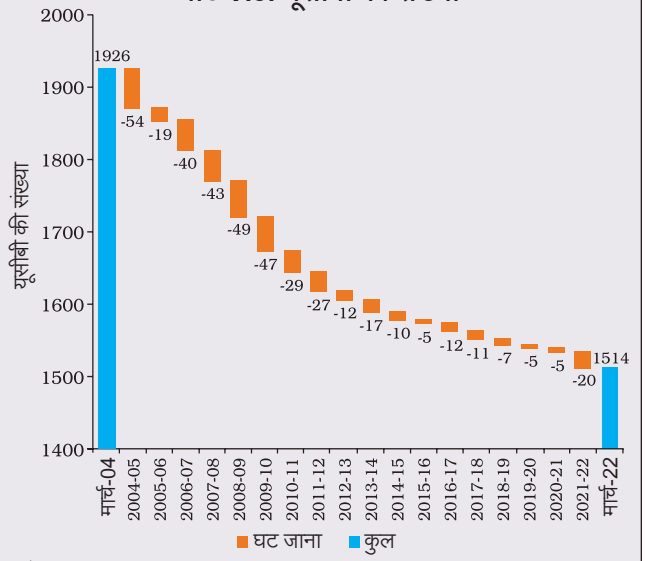

स्रोत: ऑफ साइट निगरानी संबंधी विवरणियां, आरबीआई।

कमजोरियों के साथ-साथ उनकी संरचनाओं में निहित दुर्बलता के परिणामस्वरूप नए लाइसेंस प्राप्त यूसीबी का लगभग एक-तिहाई हिस्सा रुग्ण हो गया है। वर्ष 2004-05 के बाद से, रिज़र्व बैंक ने इस क्षेत्र में समेकन की प्रक्रिया शुरू की, जिसमें अव्यवहार्य यूसीबी का उनके व्यवहार्य समकक्षों के साथ समामेलन, अव्यवहार्य संस्थाओं को बंद करना और नए लाइसेंस जारी नहीं करना शामिल है। परिणामस्वरूप, यूसीबी की संख्या उत्तरोत्तर घटती गई (चार्ट V.3)।

V.9 2021-22 के दौरान नौ गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों का वित्तीय रूप से मजबूत बैंकों के साथ स्वैच्छिक विलय कर दिया गया। वर्ष 2004-05 के बाद से, इस क्षेत्र में 145 विलय किए गए हैं, जिनमें से सर्वाधिक विलय महाराष्ट्र में हुए हैं, और इसके बाद गुजरात और आंध्र प्रदेश में हुए हैं। वर्ष 2021-22 के दौरान, 10 यूसीबी के लाइसेंस रद्द कर दिए गए, जिससे वर्ष 2015-16 से यह संख्या बढ़कर 54 हो गई। अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक (एसयूसीबी) से संबंधित एक समामेलन को छोड़कर, अन्य विलय और लाइसेंस निरस्तीकरण गैर-अनुसूचित यूसीबी (एनएसयूसीबी) से संबंधित थे, जिससे वर्ष 2020-21 में रही उनकी संख्या 1,481 से गिरकर वर्ष 2021-22 में 1,462 हो गई (चार्ट V.4)।

चार्ट V.4: यूसीबी में समेकन अभियान

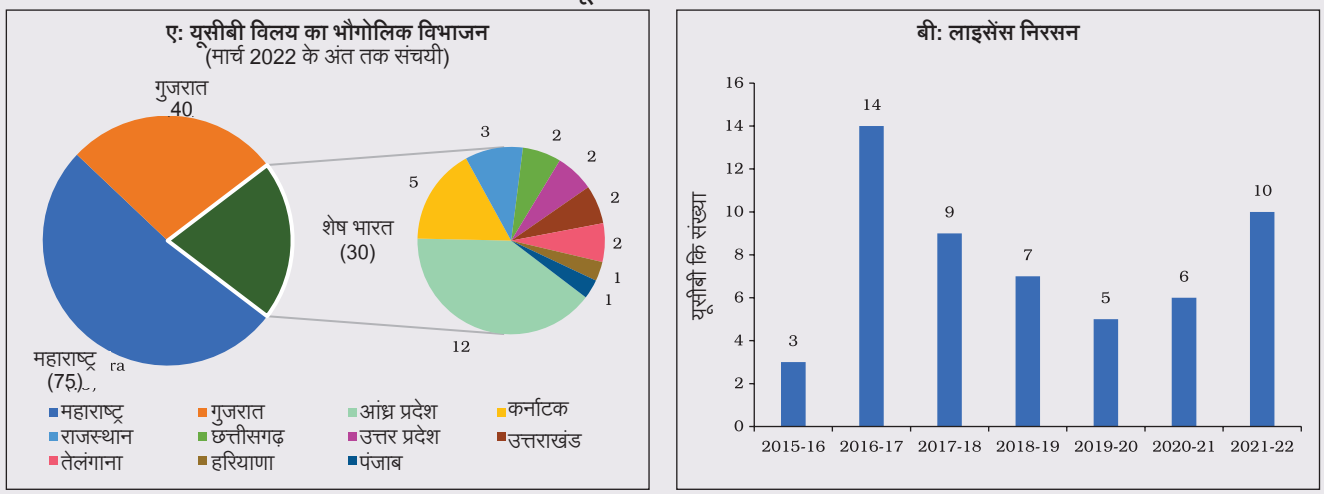

स्रोत: आरबीआई।

V.10 मुख्यत: जमा आकार के आधार पर, शहरी सहकारी बैंकों को टियर I और टियर II श्रेणियों[4,5] में विभाजित किया गया है। टीयर II बैंक इस सेगमेंट में प्रमुख खिलाड़ी बने हुए हैं और उनकी कुल आस्ति वर्ष 2016-17 में रहे 86.2 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 93.3 प्रतिशत हो गई है, हालांकि इसमें वर्ष 2021-22 में मामूली गिरावट आयी (सारणी V.2)। इसके बावजूद, टियर II यूसीबी का आस्ति-आकार, औसतन, उनके टियर I समकक्षों की तुलना में 13 गुना बड़ा है। उनका ऋण-आकार भी लगभग 14 गुना बड़ा है।

3.1 तुलन-पत्र

V.11 2004-05 से यूसीबी क्षेत्र के समेकन के परिणामस्वरूप शुरू में बड़े लाभ हुए। इस अभियान के बाद के दशक के दौरान उनके संयुक्त तुलन पत्र का आकार 11.4 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़ा, जबकि एससीबी के लिए यह 15.9 प्रतिशत था। तथापि, बाद में, दोनों खंडों की तुलन पत्र वृद्धि में नरमी आई; जहां एक ओर वर्ष 2015-16 से वर्ष 2021-22 के दौरान यूसीबी 4.8 प्रतिशत की सीएजीआर से

सारणी V.2: शहरी सहकारी बैंकों का टीयर-वार वितरण

(मार्च 2022 के अंत में)

(राशि ₹ करोड़ में)

टीयर का प्रकार	बैंकों की संख्या		जमाराशि		अग्रिम		कुल आस्तियां	
	संख्या	कुल में %	राशि	कुल में %	राशि	कुल में %	राशि	कुल में %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
टीयर I	813	53.7	40,019	7.6	23,174	7.4	53,551	8.0
टीयर II	701	46.3	4,86,001	92.4	2,91,566	92.6	6,12,935	92.0
सभी यूसीबी	**1,514**	**100.0**	**5,26,021**	**100.0**	**3,14,741**	**100.0**	**6,66,486**	**100.0**

टिप्पणी: आंकड़े अनंतिम हैं।
स्रोत: ऑफ साइट निगरानी संबंधी विवरणियां, आरबीआई।

[4] (ए) टीयर I यूसीबी को इस प्रकार परिभाषित किया गया है: i) एक ही जिले में परिचालन कर रहे और ₹100 करोड़ से कम जमा वाले बैंक ii) एक से अधिक जिलों में परिचालन कर रहे लेकिन ₹100 करोड़ से कम जमा वाले बैंक को भी टीयर I माना जाएगा, बशर्ते निकटवर्ती जिलों में उसकी शाखाएं हों और एक जिले में शाखाओं की जमा और अग्रिम अलग से बैंक की कुल जमा और अग्रिम का कम से कम 95 प्रतिशत हिस्सा हो, और iii) ₹100 करोड़ से कम जमा वाले बैंक, जिनकी शाखाएँ मूल रूप से एक ही जिले में थीं लेकिन बाद में, जिले के पुनर्गठन के कारण ये बहु-जिला वाले बन गए, उन्हें भी टीयर I यूसीबी के रूप में माना जा सकता है।

(बी) अन्य सभी यूसीबी को टियर II यूसीबी के रूप में परिभाषित किया गया है।

[5] जुलाई 2022 में, रिज़र्व बैंक ने यूसीबी के लिए चार स्तरीय संरचना को अपनाने की घोषणा की।

बढ़ी, वहीं दूसरी ओर एससीबी में 7.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई (चार्ट V.5)। इस अवधि के दौरान चक्रीय मंदी के अलावा, तुलन पत्र वृद्धि में इस गिरावट का श्रेय फिनटेक, लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) जैसे अन्य योग्य खिलाड़ियों से प्रतिस्पर्धा को दिया जा सकता है।

V.12 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के तुलन पत्र में तेजी के विपरीत, वर्ष 2021-22 के दौरान, मुख्य रूप से एसयूसीबी के तुलन पत्र में संकुचन के कारण, शहरी सहकारी बैंकों के आस्ति-आकार में कमी आई (सारणी V.3)।

V.13 लगभग दो दशकों में पहली बार वर्ष 2021-22 के दौरान जमाराशियों में कमी आई, जिससे शहरी सहकारी बैंकों के तुलन पत्र में गिरावट आई। वर्ष 2020-21 का उच्च आधार महामारी से प्रेरित एहतियात के तौर पर की गयी जमाराशियों

चार्ट V.5: आस्ति वृद्धि

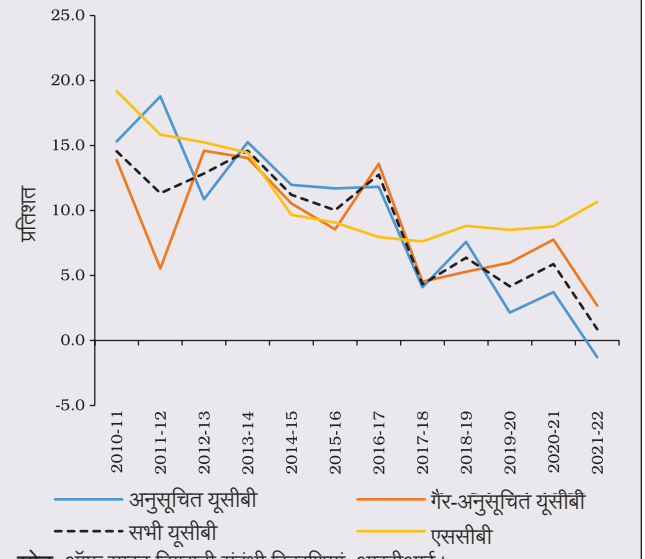

स्रोत: ऑफ साइट निगरानी संबंधी विवरणियां, आरबीआई।

सारणी V.3: शहरी सहकारी बैंकों के तुलन-पत्र
(मार्च के अंत में)

(राशि ₹ करोड़ में)

मदें	अनुसूचित यूसीबी		गैर-अनुसूचित यूसीबी		सभी यूसीबी		वृद्धि दर (%) सभी यूसीबी	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2020-21	2021-22
1	2	3	4	5	6	7	8	9
देयताएं								
1) पूंजी	4,467	4,193	9,844	10,065	14,311	14,258	1.4	-0.4
	(1.5)	(1.4)	(2.7)	(2.7)	(2.2)	(2.1)		
2) आरक्षित निधियां और अधिशेष	15,536	19,405	22,848	22,947	38,384	42,352	15.2	10.3
	(5.1)	(6.5)	(6.4)	(6.2)	(5.8)	(6.4)		
3) जमाराशियां	2,39,579	2,34,080	2,89,650	2,91,940	5,29,229	5,26,021	5.7	-0.6
	(79.4)	(78.6)	(80.7)	(79.2)	(80.1)	(78.9)		
4) उधारियां	4,755	5,418	333	242	5,089	5,660	-4.7	11.2
	(1.6)	(1.8)	(0.1)	(0.1)	(0.8)	(0.8)		
5) अन्य देयताएं और प्रावधान	37,455	34,810	36,280	43,385	73,736	78,196	4.6	6.0
	(12.4)	(11.7)	(10.1)	(11.8)	(11.2)	(11.7)		
आस्तियां								
1) उपलब्ध नकदी	1,676	1,855	4,230	4,426	5,906	6,281	1.2	6.3
	(0.6)	(0.6)	(1.2)	(1.2)	(0.9)	(0.9)		
2) आरबीआई में शेष जमाराशि	11,131	12,404	3,382	4,039	14,514	16,443	15.2	13.3
	(3.7)	(4.2)	(0.9)	(1.1)	(2.2)	(2.5)		
3) बैंकों में शेष जमाराशि	21,888	23,176	48,189	47,330	70,077	70,506	5.8	0.6
	(7.3)	(7.8)	(13.4)	(12.8)	(10.6)	(10.6)		
4) मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय जमाराशि	5,087	3,505	1,910	1,488	6,998	4,993	-16.6	-28.6
	(1.7)	(1.2)	(0.5)	(0.4)	(1.1)	(0.7)		
5) निवेश	80,297	81,128	1,00,728	1,06,574	1,81,025	1,87,702	12.1	3.7
	(26.6)	(27.2)	(28.1)	(28.9)	(27.4)	(28.2)		
6) ऋण और अग्रिम	1,43,175	1,42,627	1,70,786	1,72,114	3,13,961	3,14,741	2.8	0.2
	(47.4)	(47.9)	(47.6)	(46.7)	(47.5)	(47.2)		
7) अन्य आस्तियां	38,538	33,211	29,729	32,608	68,267	65,819	6.3	-3.6
	(12.8)	(11.1)	(8.3)	(8.8)	(10.3)	(9.9)		
कुल देयताएं/ आस्तियां	3,01,793	2,97,906	3,58,955	3,68,580	6,60,748	6,66,486	5.9	0.9
	(100.0)	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**		

टिप्पणियां: 1. मार्च 2022 से संबंधित आंकड़े अनंतिम हैं।
2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल देयताएं/ आस्तियां (प्रतिशत में) के अनुपात में है।
3. पूर्णांकन के कारण कुल जोड़ घटकों के जोड़ से भिन्न हो सकता है।

स्रोत: ऑफ साइट निगरानी संबंधी विवरणियां, आरबीआई।

चार्ट V.6: जमाराशि एवं अग्रिम: यूसीबी

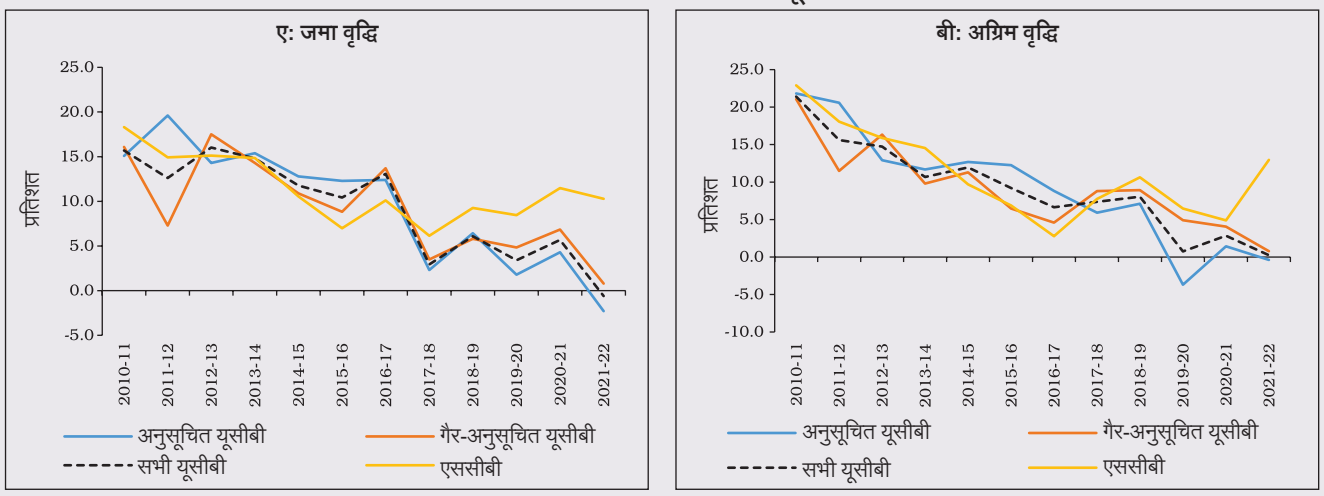

स्रोत: ऑफ साइट निगरानी संबंधी विवरणियां, आरबीआई।

को दर्शाता है, जो वर्ष 2021-22 के दौरान सामान्य हो गया। आस्ति पक्ष में, ऋण और अग्रिम तथा निवेश दोनों में गिरावट आई (चार्ट V.6)।

V.14 एससीबी की तुलना में, यूसीबी, और विशेष रूप से एनएसयूसीबी का ऋण-जमा (सी-डी) अनुपात, जमा पर अधिक निर्भरता और कम ऋण वितरण के कारण हमेशा काफी कम रहा है। हालांकि, लगातार तीन वर्षों तक गिरावट के बाद, यूसीबी का सी-डी अनुपात वर्ष 2021-22 में बढ़ गया। यह मुख्य रूप से एसयूसीबी की जमाराशियों में संकुचन के कारण था (चार्ट V.7)।

V.15 समेकन अभियान शुरू किए जाने से पहले, यूसीबी की संख्या के संदर्भ में, आस्ति-आकार दो मॉडल वाला था: ₹25 करोड़ से ₹50 करोड़ और ₹100 करोड़ से ₹250 करोड़। हालांकि, तब से वितरण दायीं दिशा में स्थानांतरित हो गया है, जो उच्चतर स्तर पर आस्ति संकेंद्रण का संकेत देता है (चार्ट V.8)।

चार्ट V.7: ऋण-जमा अनुपात: यूसीबी बनाम एससीबी

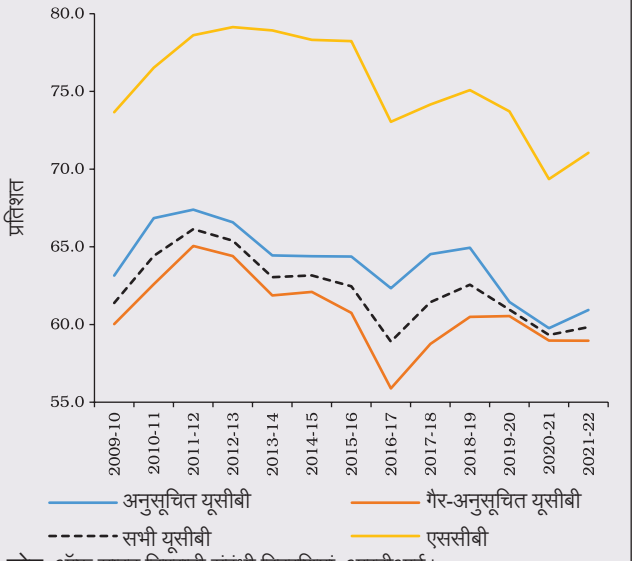

स्रोत: ऑफ साइट निगरानी संबंधी विवरणियां, आरबीआई।

चार्ट V.8: आस्ति के आकार के अनुसार यूसीबी का विभाजन

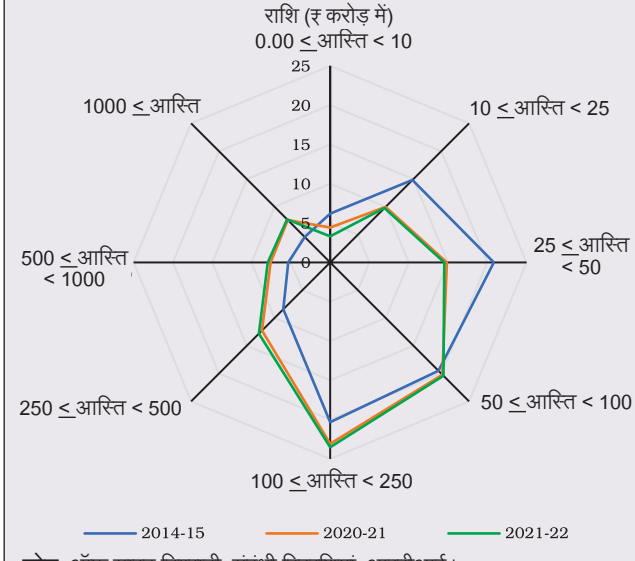

स्रोत: ऑफ साइट निगरानी संबंधी विवरणियां, आरबीआई।

चार्ट V.9: यूसीबी की जमाराशियां और अग्रिम का वितरण
(मार्च अंत तक)

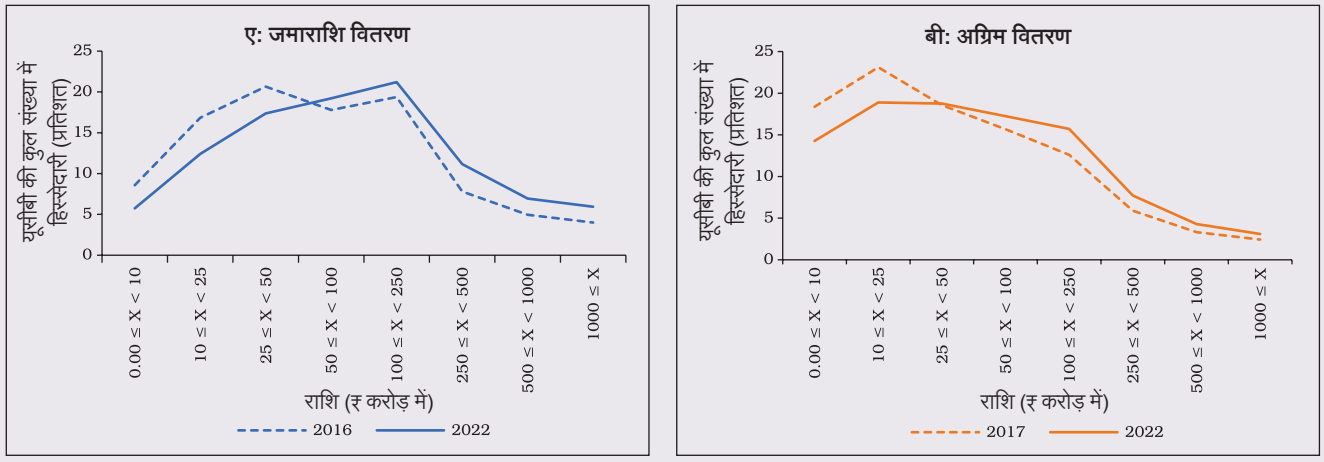

स्रोत: ऑफ साइट निगरानी संबंधी विवरणियां, आरबीआई।

V.16 शहरी सहकारी बैंकों की संख्या के संदर्भ में, वर्ष 2015-16 में जमाराशियों का मॉडल वर्ग ₹25 करोड़ से ₹50 करोड़ था। पिछले कुछ वर्षों में यह मार्च 2022 के अंत में ₹100 करोड़ से ऊपर उठते हुए, ₹250 करोड़ तक पहुंच गया है (चार्ट V.9ए)।

V.17 अग्रिमों के मामले में, वर्ष 2016-17 में मॉडल वर्ग ₹10 करोड़ से ₹25 करोड़ था, जो ₹10 करोड़ से ₹25 करोड़ और ₹25 करोड़ से ₹50 करोड़ वाले वर्गों में मार्च 2022 के अंत में उच्चतम शेयर दर्ज करते हुए, द्विमॉडल बन गया है। (सारणी V.4 और चार्ट V.9बी)।

सारणी V.4: जमाराशियों और अग्रिमों के आकार के अनुसार यूसीबी का विभाजन
(31 मार्च 2022 के अंत में)

(राशि ₹ करोड़ में)

जमाराशियां	यूसीबी की संख्या		कुल जमाराशि		अग्रिम	यूसीबी की संख्या		कुल जमाराशि	
	संख्या	% हिस्सेदारी	संख्या	% हिस्सेदारी		संख्या	% हिस्सेदारी	संख्या	% हिस्सेदारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0.00 ≤ ज < 10	87	5.7	532	0.1	0.00 ≤ अ < 10	216	14.3	1,241	0.4
10 ≤ ज < 25	188	12.4	3,257	0.6	10 ≤ अ < 25	286	18.9	4,895	1.6
25 ≤ ज < 50	263	17.4	9,793	1.9	25 ≤ अ < 50	284	18.8	10,081	3.2
50 ≤ ज < 100	291	19.2	20,799	4.0	50 ≤ अ < 100	261	17.2	18,892	6.0
100 ≤ ज < 250	321	21.2	51,128	9.7	100 ≤ अ < 250	238	15.7	37,807	12.0
250 ≤ ज < 500	169	11.2	59,480	11.3	250 ≤ अ < 500	117	7.7	40,226	12.8
500 ≤ ज < 1000	105	6.9	72,351	13.8	500 ≤ अ < 1000	65	4.3	44,863	14.3
1000 ≤ ज	90	5.9	3,08,681	58.7	1000 ≤ अ	47	3.1	1,56,736	49.8
कुल	**1,514**	**100.0**	**5,26,021**	**100.0**	**कुल**	**1,514**	**100.0**	**3,14,741**	**100.0**

टिप्पणियां: 1. आंकड़े अनंतिम हैं।
2. "ज" और "अ" क्रमशः जमाराशि और अग्रिम की राशि को दर्शाते हैं।
3. पूर्णांकन के कारण कुल जोड़ घटकों के जोड़ से भिन्न हो सकता है।

स्रोत: ऑफ साइट निगरानी संबंधी विवरणियां, आरबीआई।

सारणी V.5: शहरी सहकारी बैंकों द्वारा निवेश

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	बकाया राशि (मार्च अंत में)			घट-बढ़ (%)	
	2020	2021	2022	2020-21	2021-22
1	2	3	4	5	6
कुल निवेश (ए+बी)	**1,61,696**	**1,81,025**	**1,87,702**	**12.0**	**3.7**
	(100.0)	**(100.0)**	**(100.0)**		
ए. एसएलआर निवेश (i से iii)	**1,42,093**	**1,61,477**	**1,67,893**	**13.6**	**4.0**
	(87.9)	**(89.2)**	**(89.4)**		
i. केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां	96,471	1,02,033	1,04,728	5.8	2.6
	(59.7)	(56.4)	(55.8)		
II. राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	44,428	58,951	62,643	32.7	6.3
	(27.5)	(32.6)	(33.4)		
III. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	1,194	492	522	-58.7	6.0
	(0.7)	(0.3)	(0.3)		
बी. एसएलआर से इतर निवेश	**19,603**	**19,549**	**19,809**	**-0.3**	**1.3**
	(12.1)	**(10.8)**	**(10.6)**		

टिप्पणियां: 1. वर्ष 2022 के लिए आंकड़े अनंतिम हैं।
2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल निवेश के अनुपात (प्रतिशत में) को दर्शाते हैं।
स्रोत: ऑफ साइट निगरानी संबंधी विवरणियां, आरबीआई।

V.18 यूसीबी की तुलना में, एसयूसीबी के निवेश में तीव्र कमी उनके जमा आधार में संकुचन को दर्शाती है (सारणी V.5 और चार्ट V.10)।

चार्ट V.10: यूसीबी के निवेश

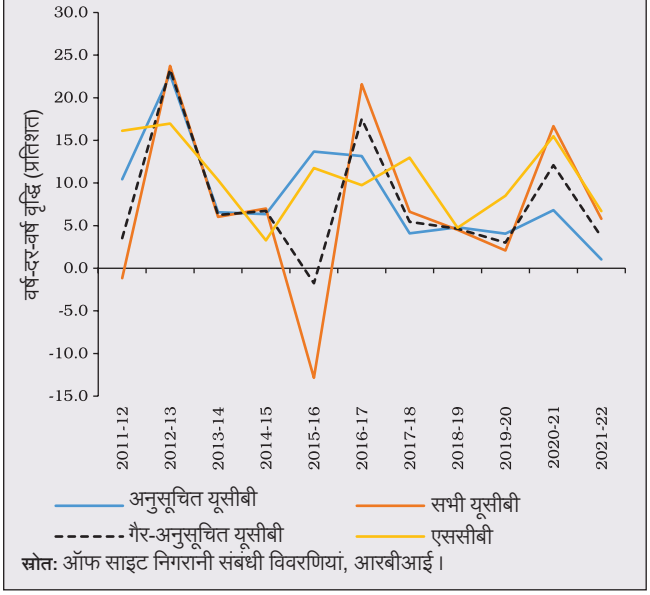

स्रोत: ऑफ साइट निगरानी संबंधी विवरणियां, आरबीआई।

3.2 सुदृढ़ता

V.19 वर्ष 2021-22 के दौरान यूसीबी पर जुर्माना लगाने के दृष्टांत विगत वर्ष के 43 से बढ़कर 145 हो गए। तदनुसार, जुर्माने की राशि में पिछले वर्ष की गिरावट की तुलना में 211 प्रतिशत की वृद्धि हुई (सारणी IV.15 देखें)। निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) द्वारा वर्ष 2021-22 के दौरान निपटाए गए दावे पूरी तरह से सहकारी बैंकों से संबंधित थे और इसमें पिछले वर्ष की तुलना में आठ गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। यह आंशिक रूप से डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 में संशोधन को दर्शाता है, जिसने जमाकर्ताओं के बीमाकृत राशि के समयबद्ध संवितरण की सुविधा प्रदान की (पैरा IV.86 देखें)।

V.20 सीएएमईएलएस-आधारित रेटिंग प्रणाली[6] को वर्ष 2019 में संशोधित किया गया था, जिसके तहत यूसीबी को ए/बी+/बी/सी/डी (प्रदर्शन के घटते क्रम में) की रेटिंग दी गई है। मार्च 2022 के अंत में, 'बी' श्रेणी संख्या-वार और कारोबार (जमा और अग्रिम का योग) के अनुसार मॉडल वर्ग में थी। हालांकि,

[6] सीएएमईएलएस (पूँजी पर्याप्तता, आस्ति गुणवत्ता, प्रबंधन, अर्जन, चलनिधि और सिस्टम एवं नियंत्रण) रेटिंग मॉडल में इसका वर्तमान स्वरूप अप्रैल 2008 में यूसीबी पर लागू हो गया।

सारणी V.6: यूसीबी का रेटिंग-वार वितरण
(मार्च 2022 के अंत में)

(राशि ₹ करोड़ में)

रेटिंग	संख्या		जमाराशियां		अग्रिम	
	बैंक	कुल में % हिस्सेदारी	राशि	कुल में % हिस्सेदारी	राशि	कुल में % हिस्सेदारी
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
ए	153	10.1	30,240	5.7	17,190	5.5
बी+	203	13.4	83,152	15.8	49,642	15.8
बी	740	48.9	2,50,292	47.6	1,52,571	48.5
सी	345	22.8	1,48,925	28.3	85,794	27.3
डी	73	4.8	13,411	2.5	9,545	3.0
कुल	1,514	100.0	5,26,021	100.0	3,14,741	100.0

टिप्पणी: 1. आंकड़े अनंतिम हैं।
2. पूर्णांकन के कारण कुल जोड़ घटकों के जोड़ से भिन्न हो सकता है।
3. रेटिंग, ऑफसाइट रिटर्न में रिपोर्ट किए गए और यूसीबी से संग्रहित किए गए नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों पर आधारित हैं।
4. प्रतिशत अंतर में थोड़ी भिन्नता हो सकती है क्योंकि पूर्ण संख्याओं का करोड़ रुपये में पूर्णांकन किया गया है।

स्रोत: ऑफ साइट निगरानी संबंधी विवरणियां, आरबीआई।

पिछले वर्ष की तुलना में, कुल में इसकी हिस्सेदारी घट गई (सारणी V.6)। इन वर्षों में, कुल कारोबार में वितरण 'सी' श्रेणी की ओर अग्रसर होकर दाईं ओर स्थानांतरित हो गई है (चार्ट V.11)।

सारणी V.7: यूसीबी का सीआरएआर-वार वितरण
(मार्च 2022 के अंत में)

(बैंकों की संख्या)

सीआरएआर (प्रतिशत में)	अनुसूचित यूसीबी	गैर-अनुसूचित यूसीबी	सभी यूसीबी
1	2	3	4
सीआरएआर < 3	4	58	62
3 <= सीआरएआर < 6	0	12	12
6 <= सीआरएआर < 9	0	16	16
9 <= सीआरएआर < 12	7	115	122
12 <= सीआरएआर	41	1,261	1,302
कुल	**52**	**1,462**	**1,514**

टिप्पणी: आंकड़े अनंतिम हैं।
स्रोत: ऑफ साइट निगरानी संबंधी विवरणियां, आरबीआई।

3.3 पूँजी पर्याप्तता

V.21 मार्च 2022 के अंत में 94 प्रतिशत यूसीबी ने जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) के लिए पूँजी को 9 प्रतिशत के विनियामकीय न्यूनतम से ऊपर बनाए रखा (सारणी V.7)। पिछले दशक में यूसीबी के पूँजी बफर में सुधार हुआ है और विनियामकीय आवश्यकताओं को पूरा करने में कुछ बैंक असफल हुए हैं (चार्ट V.12)।

चार्ट V.11: शहरी सहकारी बैंकों की संख्या और कारोबार का वितरण - रेटिंग के आधार पर (मार्च अंत तक)

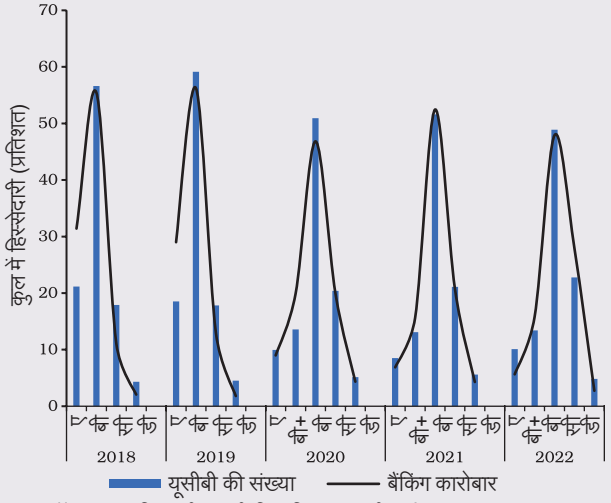

स्रोत: ऑफ साइट निगरानी संबंधी विवरणियां, आरबीआई।

चार्ट V.12: 9 प्रतिशत से कम सीआरएआर वाले यूसीबी की हिस्सेदारी

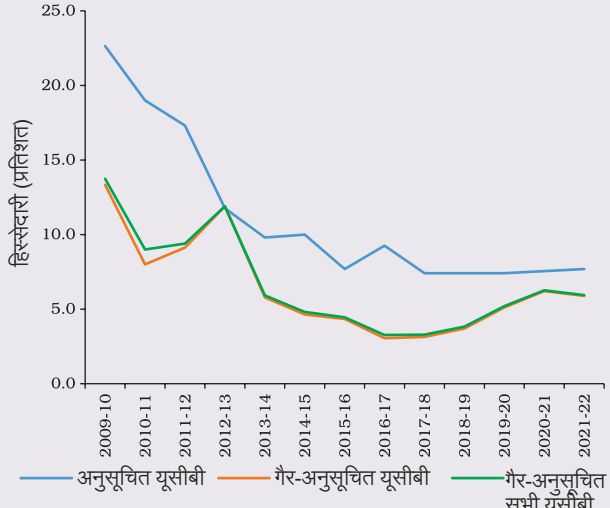

स्रोत: ऑफ साइट निगरानी संबंधी विवरणियां, आरबीआई।

सारणी V.8: यूसीबी की घटक-वार पूंजी पर्याप्तता
(मार्च के अंत में)

(राशि ₹ करोड़ में)

		अनुसूचित यूसीबी		गैर-अनुसूचित यूसीबी		सभी यूसीबी	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	पूंजीगत निधियां	**13,520**	**20,955**	**25,543**	**27,916**	**39,063**	**48,871**
	i) टीयर I पूंजी	7,758	15,019	22,010	24,006	29,768	39,025
	ii) टीयर ii पूंजी	5,762	5,935	3,533	3,910	9,295	9,845
2	जोखिम भारित आस्तियां	**1,45,352**	**1,46,925**	**1,67,243**	**1,65,940**	**3,12,594**	**3,12,865**
3	सीआरएआर (2 के % के रूप में क्र. सं. 1)	**9.3**	**14.3**	**15.3**	**16.8**	**12.5**	**15.6**
	जिसमें से:						
	टीयर I	5.3	10.2	13.2	14.5	9.5	12.5
	टीयर II	4.0	4.0	2.1	2.4	3.0	3.1

टिप्पणी: वर्ष 2022 के लिए आंकड़े अनंतिम हैं।
स्रोत: ऑफ साइट निगरानी संबंधी विवरणियां, आरबीआई।

V.22 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान एसयूसीबी ने टिअर I पूँजी में वृद्धि के साथ, अपनी पूँजीगत स्थितियों में काफी सुधार किया। हालांकि यूसीबी क्षेत्र का सीआरएआर अभी भी एससीबी से कम है, फिर भी यह क्षेत्र टियर II से IV बैंकों[7] के लिए उच्च सीआरएआर की संशोधित विनियामकीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार है (सारणी V.8)।

3.4 आस्ति गुणवत्ता

V.23 सकल अनर्जक आस्ति (जीएनपीए) अनुपात द्वारा मापी गई यूसीबी की आस्ति गुणवत्ता में वर्ष 2015-16 से वर्ष 2020-21 के दौरान लगातार गिरावट आई, लेकिन वर्ष 2021-22 में सकल अनर्जक आस्तियों की राशि में गिरावट आने से वर्ष 2012-13 के बाद पहली बार इसमें सुधार हुआ। एसयूसीबी और एनएसयूसीबी दोनों के लिए प्रावधानीकरण आवश्यकताओं को भी कम कर दिया गया है। हालांकि यूसीबी ने सावधानी दिखाई और उनके प्रावधान कवरेज अनुपात में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हुई, लेकिन यह अभी भी एससीबी की तुलना में नीचे ही है (सारणी V.9)।

V.24 मार्च 2022 के अंत में यूसीबी के कुल निधिक ऋणों का 26 प्रतिशत और उनके एनपीए का 32 प्रतिशत उन बड़े उधार खातों से उत्पन्न हुआ जिनका ₹5 करोड़ और उससे अधिक

सारणी V.9: यूसीबी की अनर्जक आस्तियां
(मार्च अंत में)

क्र. सं	मद	अनुसूचित यूसीबी		गैर-अनुसूचित यूसीबी		सभी यूसीबी	
		2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सकल एनपीए (₹ करोड़)	15,047	10,678	22,950	19,794	37,996	30,473
2	सकल एनपीए अनुपात (%)	10.5	7.5	13.4	11.6	12.1	9.7
3	निवल एनपीए (₹ करोड़)	5,746	4,116	11,037	8,798	16,783	12,914
4	निवल एनपीए अनुपात (%)	4.3	3.0	7.0	5.6	5.8	4.4
5	प्रावधानीकरण (₹ करोड़)	9,537	6,983	12,848	12,179	22,385	19,162
6	प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात (%)	63.4	65.4	56.0	61.5	58.9	62.9

टिप्पणियां: वर्ष 2021-22 के लिए आंकड़े अनंतिम हैं।
स्रोत: ऑफ साइट निगरानी संबंधी विवरणियां, आरबीआई।

[7] रिज़र्व बैंक ने 19 जुलाई 2022 को यूसीबी के लिए एक संशोधित विनियामकीय ढांचे की घोषणा की। तदनुसार, सभी यूसीबी के लिए सीआरएआर - टीयर-1 यूसीबी को छोड़कर - को 9 प्रतिशत से संशोधित कर 12 प्रतिशत कर दिया गया। हालांकि रिज़र्व बैंक ने सूचित किया कि अधिकांश बैंक पहले से ही इस मानदंड को पूरा करते हैं एवं जिन बैंकों के पास वर्तमान में पर्याप्त पूँजी बफर नहीं है उनके लिए मार्च 2026 के अंत तक निर्धारित किया गया है।

का एक्सपोजर था। इन उधारकर्ताओं के लिए एनएसयूसीबी का एक्सपोजर मार्च 2022 के अंत में उनके कुल ऋण का 10 प्रतिशत से कम था जबकि एसयूसीबी का एक्सपोजर 47 प्रतिशत था। बड़े उधार खातों से निकलने वाले यूसीबी के जीएनपीए अनुपात में गिरावट आई, जो मुख्यत: एसयूसीबी में गिरावट के कारण थी। हालांकि, एनएसयूसीबी के मामले में यह अनुपात उच्च बना हुआ है और हाल ही में इसमें और भी गिरावट आई है (चार्ट V.13)।

चार्ट V.13 बड़े उधार खातों में दबाव

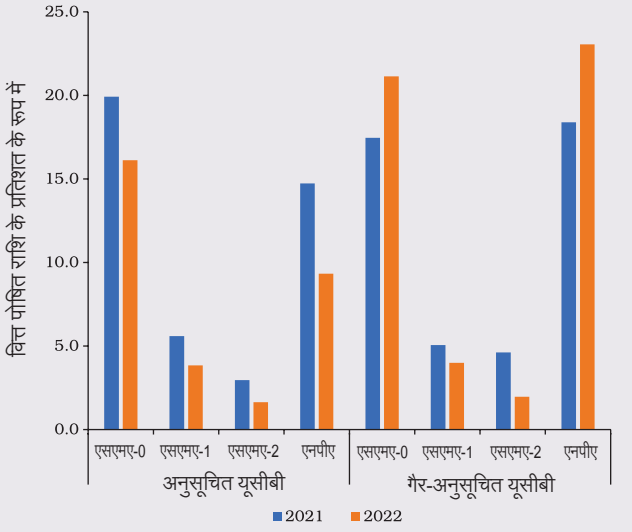

स्रोत: केंद्रीय बृहत ऋण सूचना भंडार (सीआरआईएलसी) डेटाबेस।

3.5 वित्तीय प्रदर्शन और लाभप्रदता

V.25 कम ब्याज दर व्यवस्था में कमज़ोर ऋण वृद्धि ने वर्ष 2021-22 में यूसीबी की ब्याज आय को कम किया। हालांकि, ब्याज व्यय में संकुचन और भी तेज था जिससे उनकी लाभप्रदता में सुधार हुआ। कर्ज में डूबे और दबावग्रस्त एसयूसीबी के लघु वित्त बैंक के साथ समामेलन से भी लाभप्रदता में सुधार लाने में मदद मिली। दूसरी ओर, विशेष रूप से कर्मचारियों की लागत में हुई वृद्धि से गैर-ब्याज व्यय में वृद्धि और गैर-ब्याज आय में तेजी से आई कमी ने मिलकर लाभप्रदता को शिथिल किया (सारणी V.10)।

सारणी V.10: अनुसूचित और गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों का वित्तीय निष्पादन

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	अनुसूचित यूसीबी		गैर-अनुसूचित यूसीबी		सभी यूसीबी		सभी यूसीबी घट-बढ़ (%)
	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2021-22
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
ए. कुल आय (i+ii)	**22,301**	**20,743**	**30,148**	**29,879**	**52,449**	**50,622**	**-3.5**
	(100.0)	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	
i. ब्याज से होने वाली आय	19,463	18,551	27,837	28,022	47,300	46,573	-1.5
	(87.3)	(89.4)	(92.3)	(93.8)	(90.2)	(92.0)	
ii. ब्याज से इतर होने वाली आय	2,838	2,192	2,311	1,857	5,149	4,049	-21.4
	(12.7)	(10.6)	(7.7)	(6.2)	(9.8)	(8.0)	
बी. कुल व्यय (i+ii)	**18,884**	**17,017**	**25,773**	**24,875**	**44,657**	**41,892**	**-6.2**
	(100.0)	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	
i. ब्याज से होने वाली व्यय	13,503	11,398	18,613	17,311	32,116	28,709	-10.6
	(71.5)	(67.0)	(72.2)	(69.6)	(71.9)	(68.5)	
ii. ब्याज से इतर व्यय	5,381	5,619	7,160	7,565	12,541	13,183	5.1
	(28.5)	(33.0)	(27.8)	(30.4)	(28.1)	(31.5)	
जिसमें से: स्टाफ पर व्यय	2,745	2,876	3,923	4,144	6,668	7,020	5.3
सी. लाभ							
i. परिचालनगत लाभ की राशि	3,417	3,727	4,375	5,004	7,792	8,730	12.0
ii. प्रावधान, आकस्मिक निधियां	2,242	1,921	2,584	2,805	4,826	4,726	-2.1
iii. करों के लिए प्रावधान	597	306	811	817	1,408	1,124	-20.2
iv. कर पूर्व निवल लाभ राशि	1,175	1,805	1,791	2,199	2,966	4,004	35.0
v. कर पश्चात निवल लाभ राशि	578	1,499	980	1,382	1,558	2,881	85.0

टिप्पणियां: 1. वर्ष 2021-22 से संबंधित आंकड़े अनंतिम हैं।
2. पूर्णांकन के कारण कुल जोड़, घटकों के जोड़ से भिन्न हो सकता है।
3. प्रतिशत घट-बढ़ थोड़ा भिन्न हो सकता है क्योंकि निरपेक्ष संख्याओं को रु करोड़ में पूर्णांकित कर दिया गया है।
4. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल आय/ व्यय के अनुपात को दर्शाते हैं (प्रतिशत में)।

स्रोत: ऑफ साइट निगरानी संबंधी विवरणियां, आरबीआई।

सारणी V.11: यूसीबी के चुनिंदा लाभप्रदता संकेतक

(प्रतिशत)

संकेतक	अनुसूचित यूसीबी		गैर-अनुसूचित यूसीबी		सभी यूसीबी	
	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22
1	2	3	4	5	6	7
आस्तियों पर प्रतिलाभ	0.19	0.50	0.28	0.38	0.24	0.43
इक्विटी पर प्रतिलाभ	2.94	6.88	3.22	4.21	3.11	5.27
निवल ब्याज मार्जिन	2.01	2.39	2.67	2.94	2.36	2.69

टिप्पणियां: वर्ष 2021-22 से संबंधित आंकड़े अनंतिम हैं।
स्रोत: ऑफ साइट निगरानी संबंधी विवरणियां, आरबीआई।

V.26 यूसीबी की लाभप्रदता के प्रमुख उपायों - आस्ति पर प्रतिलाभ (आरओए) और इक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओई)- में लगातार दूसरे वर्ष सुधार हुआ (सारणी V.11 और चार्ट V.14)। जमाराशियों की औसत लागत में गिरावट, साथ ही अग्रिमों पर औसत प्रतिलाभ की कीमतों में वृद्धि होने के कारण एसयूसीबी की लाभप्रदता में सुधार हुआ (परिशिष्ट सारणी V.1)।

3.6 प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार

V.27 सहकारी बैंकों की जमीनी स्तर की मजबूत उपस्थिति, वित्तीय समावेश को आगे बढ़ाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को सुगम बनाती है। यूसीबी के लिए प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को ऋण देने संबंधी मानदंड 13 मार्च 2020 को संशोधित किए गए थे –

चार्ट V.14 लाभप्रदता संकेतक - एसयूसीबी बनाम एनएसयूसीबी

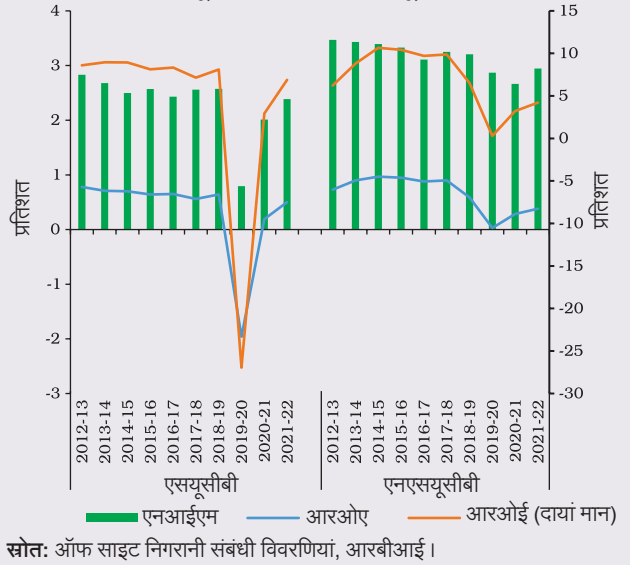

स्रोत: ऑफ साइट निगरानी संबंधी विवरणियां, आरबीआई।

जिसके तहत उन्हें मार्च 2021, 2022, 2023 और 2024 के अंत तक समायोजित निवल बैंक ऋण का क्रमशः 45 प्रतिशत, 50 प्रतिशत, 60 प्रतिशत और 75 प्रतिशत के लक्ष्य को पूरा करना आवश्यक है।

V.28 पिछले एक दशक में शहरी सहकारी बैंकों द्वारा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को दिया गया ऋण हमेशा निर्धारित लक्ष्य से अधिक रहा है। यह प्रवृत्ति उच्च विनियामकीय लक्ष्य के साथ भी जारी रही और 2021-22 के दौरान यूसीबी के उधार का 55 प्रतिशत इस क्षेत्र को दिया गया था। एमएसएमई को इस ऋण का सबसे बड़ा हिस्सा प्राप्त हुआ (सारणी V.12)। जून 2022 में, रिज़र्व बैंक ने यूसीबी, एसटीसीबी और डीसीसीबी के लिए व्यक्तिगत आवास ऋण की सीमा बढ़ा दी। आगे जाकर यह आवास क्षेत्र को दिये जाने वाले ऋण को बढ़ावा दे सकता है।

सारणी V.12 यूसीबी द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए गए ऋण का संघटन

(मार्च के अंत में)

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	2021		2022	
	राशि	कुल अग्रिमों में हिस्सेदारी (%)	राशि	कुल अग्रिमों में हिस्सेदारी (%)
1. कृषि [(i+ii+iii)]	12,245	3.9	13,213	4.2
(i) कृषि ऋण	8,913	2.8	9,841	3.1
(ii) कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर	676	0.2	915	0.3
(iii) सहायक गतिविधियां	2,701	0.9	2,457	0.8
2. सूक्ष्म और लघु उद्यम [(i+ii+iii+iv)]	1,01,340	32.3	1,07,847	34.3
(i) सूक्ष्म उद्यम	34,301	10.9	37,681	12.0
(ii) लघु उद्यम	46,128	14.7	46,733	14.8
(iii) मध्यम उद्यम	20,547	6.5	22,894	7.3
(iv) केवीआई को अग्रिम (एमएसएमई को दिये गए अन्य वित्त सहित)	365	0.1	539	0.2
3. निर्यात ऋण	368	0.1	284	0.1
4. शिक्षा	2,374	0.8	2,629	0.8
5. आवास	25,211	8.0	26,803	8.5
6. सामाजिक गतिविधियां	1,185	0.4	1,114	0.4
7. अक्षय उर्जा	1,291	0.4	1,380	0.4
8. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत "अन्य" श्रेणी	17,694	5.6	20,012	6.4
9. कुल (1 से 8)	1,61,708	51.5	1,73,282	55.1
जिसमें से, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत कमजोर तबकों को दिया गया ऋण	33,590	10.7	34,844	11.1

टिप्पणियां: 1. वर्ष 2022 से संबंधित आंकड़े अनंतिम हैं।
2. प्रतिशत हिस्सेदारी यूसीबी के कुल ऋण के संदर्भ में है।
3. पूर्णांकन के कारण कुल जोड़, घटकों के जोड़ से भिन्न हो सकता है।
स्रोत: ऑफ साइट निगरानी संबंधी विवरणियां, आरबीआई।

चार्ट V.15: प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार

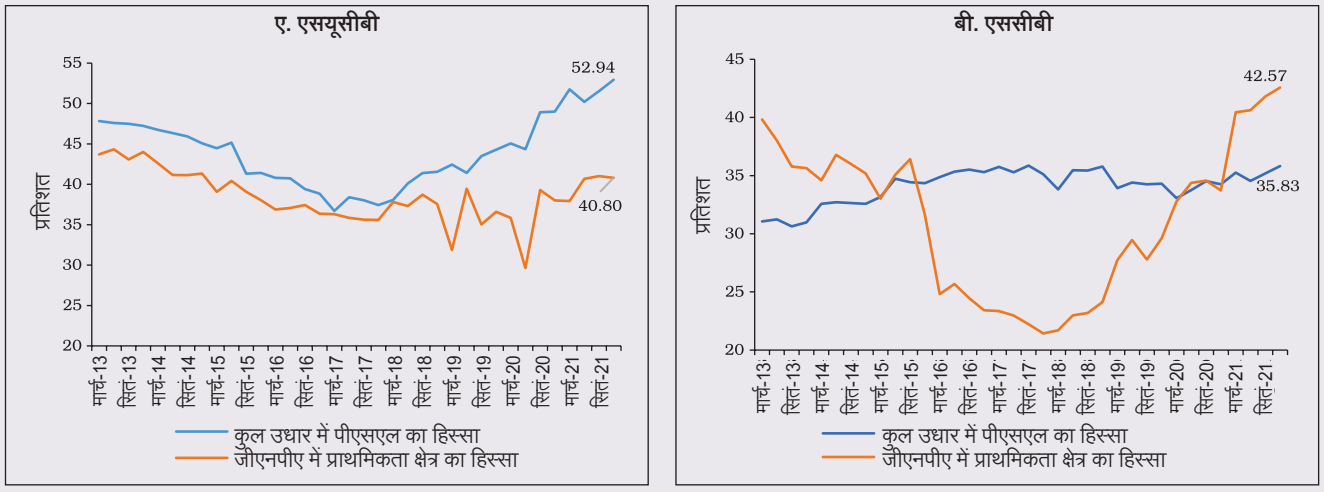

स्रोत: पर्यवेक्षी डेटा पर आधारित स्टाफ गणना।

V.29 एसयूसीबी के कुल ऋण में प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र की बढ़ती हिस्सेदारी के बावजूद उनके जीएनपीए, विशेष रूप से एससीबी की तुलना में कम रहे हैं (चार्ट V.15ए और 15बी)।

V.30 अनुभवजन्य साक्ष्य बताते हैं कि आस्ति की गुणवत्ता और पूँजी बफर एसयूसीबी की लाभप्रदता के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं और प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को दिए जाने वाले उधार इसे कमजोर नहीं करते हैं (बॉक्स V.1)।

बॉक्स V.1: अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों की लाभप्रदता के निर्धारक

अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों (एसयूबी) के लिए मार्च 2013 से दिसंबर 2021 की अवधि के लिए 54 संस्थाओं के तिमाही पैनल डाटा का उपयोग निश्चित प्रभाव पैनल प्रतिगमन फ्रेमवर्क में किया गया था। आश्रित चर यानी बैंकों की लाभप्रदता, आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए) और या विकल्प के

सारणी 1ए: एसयूसीबी की लाभप्रदता पर प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार देने का प्रभाव
मॉडल I: बैंक विशिष्ट कारक

	(1)	(2)	(3)	(4)
चर	आस्तियों पर प्रतिलाभ	एनआईएम	आस्तियों पर प्रतिलाभ	एनआईएम
पीएसएल	-0.00331 (0.00453)	0.000879 (0.00208)	-0.00466 (0.00473)	0.000587 (0.00210)
कुल जीएनपीए	-0.0284*** (0.00586)	-0.0220*** (0.00389)		
कुल आस्तियां	-0.0501 (0.367)	-0.587** (0.275)	0.0330 (0.351)	-0.466 (0.302)
सीआरएआर	0.0256*** (0.00515)	-0.00455 (0.00348)	0.0298*** (0.00730)	-0.000873 (0.00582)
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का जीएनपीए			-0.0209*** (0.00687)	-0.0139** (0.00557)
नियतांक (कोंस्टंट)	1.466 (6.221)	12.19** (4.655)	0.0164 (5.878)	10.06* (5.066)
बैंक स्थिर प्रभाव	हां	हां	हां	हां
समय स्थिर प्रभाव	हां	हां	हां	हां
निष्कर्ष	1,938	1,938	1,938	1,938
आर वर्ग	0.254	0.764	0.206	0.740
बैंको की संख्या	55	55	55	55

कोष्ठक में सुदृढ़ मानक त्रुटियाँ दी गयी हैं।
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

(जारी...)

रूप में निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) द्वारा अनुमानित है। व्याख्यात्मक चर में बैंक के विशिष्ट कारक जैसे एसयूसीबी के कुल ऋण में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार अनुपात (पीएसएल अनुपात), सकल अनर्जक आस्ति (जीएनपीए) अनुपात, कुल आस्ति, मॉडल I में सीआरएआर और प्राथमिकता क्षेत्र का जीएनपीए आदि शामिल हैं । मॉडल II में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि और मुद्रास्फीति जैसे समष्टिआर्थिक चर पर नियंत्रण कर समान संबंध का परीक्षण किया जाता है।

निष्कर्ष सुझाते हैं कि कुल जीएनपीए अनुपात और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के उधार के जीएनपीए अनुपात द्वारा मापी गई आस्ति गुणवत्ता एसयूसीबी की लाभप्रदता से विपरीत रूप से संबंधित है जबकि पूँजी बफर का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार लाभप्रदता का एक महत्वपूर्ण निर्धारक नहीं है। इनके परिणाम, मॉडल की विभिन्न विशिष्टताओं के अनुरूप हैं (सारणी 1ए)।

समष्टिआर्थिक चर पर नियंत्रण करने के बाद भी परिणाम सुसंगत रहते हैं जैसे वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि और मुद्रास्फीति (सारणी 1बी), बैंक लाभप्रदता की प्र-चक्रीयता की ओर इशारा करती है जबकि उच्च मुद्रास्फीति लाभ मार्जिन को कम करती प्रतीत होती है। परिचालन आय से गैर-ब्याज आय का अनुपात आय विविधीकरण को दर्शाता है जिससे आरओए पर उल्लेखनीय और सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

सारणी 1बी: एसयूसीबी की लाभप्रदता पर प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार देने का प्रभाव

मॉडल II: बैंक विशिष्ट कारक और समष्टि-आर्थिक नियंत्रण

चर	(1)	(2)
	आस्तियों पर प्रतिलाभ	आस्तियों पर प्रतिलाभ
पीएसएल	-0.00302	-0.00317
	(0.00452)	(0.00427)
कुल जीएनपीए	-0.0278***	-0.0281***
	(0.00600)	(0.00577)
सीआरएआर	0.0254***	0.0258***
	(0.00481)	(0.00506)
गैर-ब्याज आय से परिचालन आय		1.165**
		(0.498)
कुल आस्तियां	-0.0535	-0.00229
	(0.339)	(0.340)
वास्तविक जीडीपी	0.00555**	
	(0.00245)	
मुद्रास्फीति	-0.0138	
	(0.0106)	
डबल्यूएएलआर	0.0478	
	(0.0621)	
नियतांक (कोंस्टंट)	1.017	0.526
	(6.560)	(5.733)
बैंक स्थिर प्रभाव	हां	हां
समय स्थिर प्रभाव	नहीं	हां
निष्कर्ष	1,938	1,937
आर-वर्ग	0.209	0.265
बैंकों की संख्या	55	55

कोष्ठक में सुदृढ़ मानक त्रुटियां दी गयी हैं।

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

4. ग्रामीण सहकारी संस्थाएं

V.31 ग्रामीण ऋणग्रस्तता और गरीबी की दोहरी समस्या को दूर करने के लिए, ग्रामीण ऋण सहकारिता, सीमांत क्षेत्रों और गतिविधियों को सस्ती कीमत पर ऋण देने के लिए, एक संस्थागत तंत्र के रूप में अस्तित्व में आई। ग्रामीण सहकारी समितियों की हिस्सेदारी बढ़ रही है - कुल आस्तियों में उनकी हिस्सेदारी मार्च 2020 के अंत में 66.9 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2021 के अंत में 67.3 प्रतिशत हो गई।

V.32 ग्रामीण सहकारी बैंकों के लघु और दीर्घकालिक संस्थानों के नेटवर्क ने आउटरीच और व्यवसाय की मात्रा के कारण ग्रामीण ऋण वितरण प्रणाली में एक विशिष्ट स्थान बनाया है। जमाराशियाँ अल्पकालिक ऋण सहकारी समितियों के लिए धन का प्रमुख स्रोत हैं जबकि दीर्घकालिक ऋण सहकारी समितियाँ उधार पर बहुत अधिक निर्भर करती हैं। अल्पकालिक ग्रामीण सहकारी समितियों का वित्तीय प्रदर्शन अपेक्षाकृत बेहतर है जिसमें निवल लाभ में आनुपातिक रूप से उच्च हिस्सेदारी, एनपीए में कम हिस्सेदारी और मांग अनुपात में ऋण की उच्च वसूली भी शामिल हैं। (सारणी V.13 और चार्ट V.16)।

V.33 साथ ही, यह क्षेत्र संरचनात्मक और अस्थायी दोनों तरह की चुनौतियों से भी जूझ रहा है। जहां एक व्यापक जमाकर्ता आधार यूसीबी को अपेक्षाकृत कम लागत पर धन जुटाने में सक्षम बनाता है, वहीं ग्रामीण सहकारी समितियाँ अपने कार्यों के लिए उधार पर बहुत अधिक निर्भर हैं। मार्च 2021 के अंत में यूसीबी की देनदारियों का लगभग 1 प्रतिशत उधार था जबकि ग्रामीण सहकारी समितियों के लिए यह 29 प्रतिशत था। हालिया नरमी के बावजूद, घाटा उठाने वाली ग्रामीण सहकारी समितियों की संख्या उच्च बनी हुई है जो बड़े पैमाने पर आस्ति-गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दर्शाती है। कई संस्थानों के लिए पूँजी-पर्याप्तता भी एक कमजोर बिन्दु है।

सारणी V.13: ग्रामीण सहकारी संस्थानों का प्रोफाइल
(31 मार्च 2021के अंत में)

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	अल्पावधि			दीर्घावधि	
	एसटीसीबी	डीसीसीबी	पीएसीएस	एससीएआरडीबी (पी)	पीसीएआरडीबी(पी)
1	2	3	4	5	6
ए. सहकारी संस्थाओं की संख्या	34*	351	102,559	13	603
बी. तुलन-पत्र के संकेतक					
i. स्वाधिकृत निधियां (पूंजी+ आरक्षित निधियां)	24,425	46,773	42,311	6,142	4,227
ii. जमाराशियां	2,23,057	3,81,825	1,70,922	2,546	1,551
iii. उधारियां	1,07,207	1,08,077	1,43,044	13,293	16,144
iv. ऋण और अग्रिम	2,11,794	3,04,990	2,29,443	20,918	15,325
v. कुल देयताएं/ आस्तियां	3,77,338	5,88,914	3,34,718	27,275	31,677
सी. वित्तीय निष्पादन					
i. लाभ में रहने वाले संस्थान					
ए. संख्या	32	308	47,297	10	311
बी. लाभ की राशि	1,669	2,091	5,298	180	193
ii. हानि में रहने वाले संस्थान					
ए. संख्या	2	43	37,419	3	292
बी. लाभ की राशि	268	669	4,320	17	665
iii. समग्र लाभ(+)/हानि(-)	1,402	1,422	978	163	-473
डी. अनर्जक आस्तियां					
i. राशि	14,113	34,761	72,550	6,942	6,818
ii. बकाया ऋण के प्रतिशत के रूप में	6.7	11.4	33.5	33.2	44.5
ई. मांग-ऋण वसूली अनुपात *(प्रतिशत)**	90.5	74.9	71.1	46.5	41.8

टिप्पणियां: 1. एसटीसीबी: राज्य सहकारी बैंक डीसीसीबी: जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक; पीएसीएस: प्राथमिक कृषि ऋण समितियां; एससीएआरडीबी: राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, पीसीएआरडीबी: प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक
2. (पी) आंकड़े अनंतिम हैं।
3. * वित्तीय वर्ष 2019-20 तक , दमन और दीव एसटीसीबी के डेटा को गोवा एसटीसीबी के एक भाग के रूप में रिपोर्ट किया गया था। 31 मार्च 2021 तक की स्थिति के लिए गोवा एसटीसीबी और दमन और दीव एसटीसीबी की लेखा परीक्षा अलग से की गयी थी।
4. ** यह अनुपात बकाया अनर्जक ऋण राशि के उस हिस्से को दर्शाता है जिसकी वसूली वित्तीय वर्ष 30 जून को वसूली की जा चुकी है।

स्रोत: नाबार्ड और एनएएफसीओबी (पीएसीएस डेटा)।

4.1 अल्पावधिक ग्रामीण सहकारी संस्थाएं

V.34 अल्पावधि ऋण सहकारी समितियां अर्थात राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी), जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक (डीसीसीबी) और प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पीएसीएस) जो जमीनी स्तर पर काम करती हैं वो फसल ऋण/कार्यशील पूँजी के प्रावधान के माध्यम से सदस्यों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। वे कई गैर-वित्तीय सेवाएं जैसे इनपुट आपूर्ति, उत्पादन के भंडारण और विपणन के साथ-साथ उपभोक्ता वस्तुओं की आपूर्ति आदि भी प्रदान करती हैं।

V.35 वर्ष 2021 में एसटीसीबी द्वारा अर्जित लाभ का एक बड़ा हिस्सा दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों से प्राप्त किया गया था (परिशिष्ट सारणी V.3)। डीसीसीबी, जिनकी मध्य क्षेत्र में अपेक्षाकृत मजबूत उपस्थिति है, पश्चिमी क्षेत्र से अपने लाभ

चार्ट V.16: दीर्घावधि बनाम अल्पावधि ग्रामीण सहकारी संस्थाएं
(मार्च 2021 के अंत में)

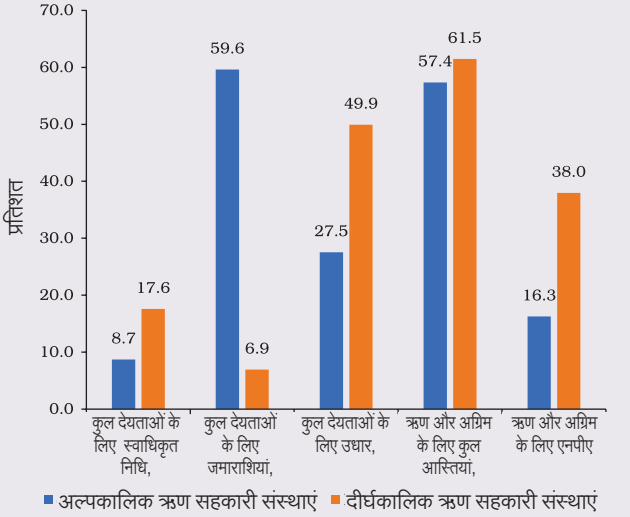

स्रोत: नाबार्ड और एनएएफएससीओबी।

का उच्चतम हिस्सा अर्जित करते हैं (परिशिष्ट सारणी V.4)। दूसरी ओर, हालांकि पीएसीएस पश्चिमी क्षेत्र में अधिक केंद्रित हैं, वे मुनाफे के लिए उत्तरी क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भर हैं (परिशिष्ट सारणी V.6)।

V.36 वित्तीय प्रदर्शन की तुलना से पता चलता है कि पीएसीएस अल्पावधि ग्रामीण सहकारी खंड में सबसे कमजोर कड़ी हैं। उधार पर उनकी उच्च निर्भरता, उच्च एनपीए अनुपात और कम वसूली अनुपात उनकी अंतर्निहित कमजोरियों की ओर इशारा करते हैं (चार्ट V.17)।

4.1.1 राज्य सहकारी बैंक

V.37 राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी) ग्रामीण सहकारी संरचना में शीर्ष संस्थाएं हैं, जो टियर II और टियर III संस्थाओं को चलनिधि और तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं, इसके अलावा वे स्वयं ग्राहकों को ऋण देते हैं। मार्च 2021 के अंत में,

चार्ट V.17: अल्पावधि ग्रामीण सहकारी संस्थाओं की तुलना (तुलन-पत्र और वित्तीय-निष्पादन)
(मार्च 2021 के अंत में)

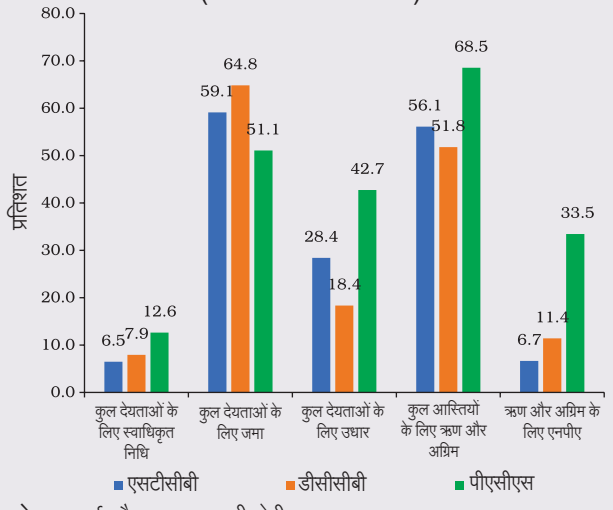

स्रोत: नाबार्ड और एनएएफएससीओबी।

35 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों[8] में उनकी 2,078 शाखाएँ थीं, जो विभिन्न कृषि और गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए ऋण प्रदान करती थीं। एसटीसीबी के कुल ऋण पोर्टफोलियो में कृषि ऋण की हिस्सेदारी 43 प्रतिशत है।

तुलन-पत्र परिचालन

V.38 राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) का तुलन पत्र 2020-21 में लगातार तीसरे वर्ष 7 प्रतिशत से अधिक बढ़ा। पिछले वर्षों की तरह, जमाराशियाँ उनकी देयताओं का मुख्य आधार बनी हुई हैं। वर्ष 2020-21 में उपलब्ध उधारी की कम लागत का लाभ उठाते हुए, उधारी में तेज वृद्धि संसाधन जुटाने की उनकी गतिशील रणनीति को भी रेखांकित करती है। हालांकि, उस समय कमजोर ऋण मांग के कारण, जुटाए गए उच्चतर वृद्धिशील संसाधनों का उपयोग ऋण और अग्रिमों के विस्तार के लिए नहीं किया जा सका। इसके बजाय, इन संसाधनों को निवेश और नकद होल्डिंगों के रूप में लगाया गया (सारणी V.14)।

V.39 वर्ष 2021-22 के लिए उपलब्ध पर्यवेक्षी डेटा, मजबूत ऋण-उठाव और तदनुरूप एसएलआर निवेश में कमी के साथ, एक पलटाव दिखाता है (सारणी V.15)।

लाभप्रदता

V.40 वर्ष 2019-20 के दौरान, ब्याज आय और खर्च किए गए ब्याज दोनों में संकुचन हुआ, लेकिन ब्याज-आय ने ब्याज-व्यय की तुलना में कहीं अधिक भरपाई की। परिणामस्वरूप, यह एसटीसीबी के लिए लाभदायक वर्ष साबित हुआ। यह वर्ष 2020-21 में उल्टा हो गया और जैसे ही ब्याज-व्यय में वृद्धि ब्याज-आय से अधिक हो गई, इस क्षेत्र में लाभप्रदता में गिरावट देखी गई।

[8] हालांकि 34 एसटीसीबी हैं तथापि जम्मू और कश्मीर राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड की केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 7 शाखाएं हैं।

सारणी V.14: राज्य सहकारी बैंकों की देयताएं और आस्तियां

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	मार्च के अंत की स्थिति		घट-बढ़ (%)	
	2020	2021	2019-20	2020-21
1	2	3	4	5
देयताएं				
1. पूंजी	7,459	8,577	0.4	15.0
	(2.2)	(2.3)		
2. आरक्षित निधियां	14,441	15,848	4.7	9.7
	(4.2)	(4.2)		
3. जमाराशियां	2,10,342	2,23,057	9.2	6.0
	(61.8)	(59.1)		
4. उधारियां	85,723	1,07,207	2.0	25.1
	(25.2)	(28.4)		
5.अन्य देयताएं	22,301	22,648	16.9	1.6
	(6.6)	(6.0)		
आस्तियां				
1. नकद और बैंक में जमा शेष	10,229	14,360	-32.6	40.4
	(3.0)	(3.8)		
2. निवेश	1,12,828	1,29,329	9.4	14.6
	(33.2)	(34.3)		
3. ऋण और अग्रिम	1,99,943	2,11,794	8.9	5.9
	(58.8)	(56.1)		
4. संचित हानि	1,232	1,405	25.0	14.0
	(0.4)	(0.4)		
5. अन्य	16,035	20,451	13.3	27.5
	(4.7)	(5.4)		
आस्तियां कुल देयताएं/ आस्तियां	**3,40,267**	**3,77,338**	**7.3**	**10.9**
	(100.0)	**(100.0)**		

टिप्पणियां: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल देयताएं/ आस्तियों के अनुपात को दर्शाते हैं (प्रतिशत में)।
2. वर्ष –दर-वर्ष प्रतिशत घट-बढ़ थोड़ी भिन्न हो सकती है क्योंकि निरपेक्ष संख्याओं का ₹ 1 करोड़ में पूर्णांकन कर दिया गया है।
3. पूर्णांकन के कारण कुल जोड़, घटकों के जोड़ से भिन्न हो सकता है।
4. वर्ष 2019-20 के दौरान, केरल की 13 डीसीसीबी (मल्लापुरम डीसीसीबी को छोड़कर) का केरल एसटीसीबी में समामेलन कर दिया गया। पिछले वर्ष के एसटीसीबी के योग में 13 डीसीसीबी के डेटा को जोड़ दिया गया है ताकि तुलना और वृद्धि दर की गणना की जा सके।

स्रोत: नाबार्ड ।

मुख्य रूप से वेतन बिलों के कारण परिचालन व्यय में वृद्धि ने मुनाफे में संकुचन को और बढ़ा दिया (सारणी V.16)।

V.41 मुनाफे में संकुचन उत्तरी क्षेत्र में सबसे तेज था। यह मुख्य रूप से जम्मू और कश्मीर के एसटीसीबी के कारण रहा, जिसने ₹ 24,751 लाख रुपये की हानि दर्ज की। दक्षिणी क्षेत्र में लाभ में आयी कमी को भी शामिल करने से, पूरे देश में हुए लाभों में कमी आ गई (परिशिष्ट सारणी V.3)।

आस्ति गुणवत्ता

V.42 वर्ष 2019-20 में गिरावट के बाद, एसटीसीबी में एनपीए वृद्धि वर्ष 2020-21 में धीमी हुई। संदेहास्पद और हानि खातों में तीव्र वृद्धि ने अवमानक आस्तियों में सुधार के लिए प्रतिसंतुलनकारी बल के रूप में कार्य किया, जिसके परिणामस्वरूप, ऋण की तुलना में एनपीए अनुपात पिछले वर्ष की तरह 6.7 प्रतिशत पर अपरिवर्तित ही रहा। पूर्वी, मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों में एनपीए अनुपात में सुधार अन्य क्षेत्रों में गिरावट से प्रतिसंतुलित हो गया था (परिशिष्ट सारणी V.3)। रिकवरी अनुपात में गिरावट इस क्षेत्र में अंतर्निहित कमजोरी को उजागर करती है (सारणी V.17)।

4.1.2 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक

V.43 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक (डीसीसीबी), जो अल्पावधिक ग्रामीण सहकारी संरचना में दूसरे स्तर का गठन

सारणी V.15: अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों के चुनिंदा तुलन-पत्र संकेतक

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20*	2020-21	2021-22
1	2	3	4	5	6	7
जमाराशियां	90,277	98,768	1,10,559	1,87,456	1,97,751	2,11,784
	(13.5)	(9.4)	(11.9)	(69.6)	(5.5)	(7.1)
ऋण	1,10,934	1,17,989	1,31,399	1,94,310	2,06,322	2,28,194
	(3.3)	(6.4)	(11.4)	(47.9)	(6.2)	(10.6)
एसएलआर निवेश	26,225	33,411	33,130	54,181	67,788	77,677
	(8.3)	(27.4)	-(0.8)	(63.5)	(25.1)	(14.6)
ऋण तथा एसएलआर निवेश का जोड़	1,37,159	1,51,400	1,64,529	2,48,492	2,74,110	3,05,871
	(4.2)	(10.4)	(8.7)	(51.0)	(10.3)	(11.6)

टिप्पणियां: 1. आंकड़े संगत वर्ष के मार्च के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार से संबंधित हैं।
2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि दर को प्रतिशत में दर्शाते हैं।
3. *: उच्च वृद्धि मुख्य रूप से केरल राज्य सहकारी बैंक के साथ 13 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के समामेलन के कारण है।

स्रोत: आरबीआई अधिनियम की धारा 42 के तहत प्रपत्र बी।

सारणी V.16 राज्य सहकारी बैंकों का वित्तीय निष्पादन

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	के दौरान		घट-बढ़ प्रतिशत	
	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21
1	2	3	4	5
ए. आय (i+ii)	**21,922**	**24,318**	**-1.6**	**10.9**
	(100.0)	**(100.0)**		
i. ब्याज से होनेवाली आय	20,014	23,177	-6.4	15.8
	(91.3)	(95.3)		
ii. अन्य आय	1,908	1,141	111.9	-40.2
	(8.7)	(4.7)		
बी. व्यय (i+ii+iii)	**20,198**	**22,916**	**-4.1**	**13.5**
	(100.0)	**(100.0)**		
i. व्ययगत ब्याज	14,871	17,318	-8.6	16.5
	(73.6)	(75.6)		
ii. प्रावधान और आकस्मिक निधियां	2,646	2,181	67.6	-17.6
	(13.1)	(9.5)		
iii. परिचालनगत व्यय	2,681	3,418	-16.4	27.5
	(13.3)	(14.9)		
जिसमें से: वेतन बिल	1,491	1,926	-14.3	29.1
	(7.4)	(8.4)		
सी. लाभ				
i. परिचालनगत लाभ	2,974	2,947	26.0	-0.9
ii. निवल लाभ	1,724	1,402	41.3	-18.7

टिप्पणियां: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल आय/ व्यय के अनुपात को दर्शाते हैं (प्रतिशत में)।
2. वर्ष-दर-वर्ष प्रतिशत घट-बढ़ थोड़ी भिन्न हो सकती है क्योंकि निरपेक्ष संख्याओं का ₹ 1 करोड़ में पूर्णांकन कर दिया गया है।
3. पूर्णांकन के कारण कुल जोड़, घटकों के जोड़ से भिन्न हो सकता है।
4. वर्ष 2019-20 के दौरान, केरल की 13 डीसीसीबी (मल्लापुरम डीसीसीबी को छोड़कर) का केरल एसटीसीबी में समामेलन कर दिया गया। पिछले वर्ष के एसटीसीबी के योग में 13 डीसीसीबी के डेटा को जोड़ दिया गया है ताकि तुलना और वृद्धि दर की गणना की जा सके।

स्रोत: नाबार्ड।

करते हैं, 20 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में 13,610 शाखाओं के नेटवर्क के साथ काम कर रहे हैं जो मुख्य रूप से मध्य क्षेत्र में केंद्रित हैं। वे व्यक्तिगत उधारकर्ताओं एवं तीसरे स्तर के संस्थानों यथा पीएसीएस को उधार देने के लिए, सार्वजनिक जमाराशियों, राज्य सहकारी बैंकों से उधारी और नाबार्ड से पुनर्वित्त के माध्यम से धन जुटाते हैं। डीसीसीबी का लगभग 60 प्रतिशत ऋण पीएसीएस के माध्यम से होता है। जमाराशि जुटाने के लिए अपने व्यापक शाखा नेटवर्क का लाभ उठाने में सक्षम होने के कारण, डीसीसीबी एसटीसीबी की तुलना में उधारी पर कम निर्भर हैं। इससे एसटीसीबी की तुलना में, सीडी अनुपात भी कम होता है, तथापि डीसीसीबी का बकाया ऋण अपेक्षाकृत बड़ा है।

सारणी V.17: राज्य सहकारी बैंकों के सुदृढ़ता संकेतक

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	मार्च के अंत की स्थिति		घट बढ़ प्रतिशत	
	2020	2021	2019-20	2020-21
1	2	3	4	5
ए. कुल एनपीए (i+ii+iii)	13,477	14,113	35.2	4.7
i. अवमानक	7,883	7,379	67.3	-6.4
	(58.5)	(52.3)		
ii. संदिग्ध	4,400	5,294	9.7	20.3
	(32.6)	(37.5)		
iii. हानि	1,195	1,440	-4.1	20.5
	(8.9)	(10.2)		
बी. ऋण की तुलना में एनपीए अनुपात (%)	**6.7**	**6.7**	**-**	**-**
सी. मांग-वसूली अनुपात (%)	**94.4**	**90.5**	**-**	**-**

टिप्पणियां: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल एनपीए में हिस्सेदारी को दर्शाते हैं (प्रतिशत में)।
2. निरपेक्ष संख्याओं का पूर्णांकन किया गया है, जिसके कारण प्रतिशत में थोड़ी भिन्नता आ सकती है।
3. पूर्णांकन के कारण कुल जोड़, घटकों के जोड़ से भिन्न हो सकता है।
4. वर्ष 2019-20 के दौरान, केरल की 13 डीसीसीबी (मल्लापुरम डीसीसीबी को छोड़कर) का केरल एसटीसीबी में समामेलन कर दिया गया। पिछले वर्ष के एसटीसीबी के योग में 13 डीसीसीबी के डेटा को जोड़ दिया गया है ताकि तुलना और वृद्धि दर की गणना की जा सके।
5. वसूली की स्थिति समान वित्तीय वर्ष की 30 जून की स्थिति के अनुसार है।

स्रोत: नाबार्ड।

तुलन-पत्र परिचालन

V.44 वर्ष 2019-20 में गिरावट के बाद, वर्ष 2020-21 में डीसीसीबी की समेकित तुलन-पत्र वृद्धि में पुनर्वृद्धि मुख्य रूप से देयताएं के पक्ष में जमा और उधारी से प्रेरित थी। यह ऋण एवं अग्रिम तथा आस्ति पक्ष में निवेश में तेजी से मेल खाता था। लगातार दूसरे वर्ष भी संचित हानियों में गिरावट एक मजबूत तुलन-पत्र का संकेत है (सारणी V.18)।

लाभप्रदता

V.45 हालांकि डीसीसीबी की आय और व्यय दोनों में गिरावट आई। हालांकि व्यय में वृद्धि आय की अपेक्षा बहुत कम थी जिसके परिणामस्वरूप लाभ में ज्यादा वृद्धि हुई (सारणी V.19)। विशेष रूप से, ब्याज आय में वृद्धि ने ब्याज व्यय में वृद्धि को पीछे छोड़ दिया जिससे निवल ब्याज आय में वृद्धि हुई।

सारणी V.18: जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की देयताएं और आस्तियां

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	मार्च के अंत की स्थिति		घट बढ़ प्रतिशत	
	2020	2021	2019-20	2020-21
1	2	3	4	5
देयताएं				
1. पूंजी	20,913 (3.9)	22,391 (3.8)	3.9	7.1
2. आरक्षित निधियां	22,332 (4.2)	24,381 (4.1)	7.5	9.2
3. जमाराशियां	3,45,682 (64.5)	3,81,825 (64.8)	7.7	10.5
4. उधारियां	97,448 (18.2)	1,08,077 (18.4)	4.8	10.9
5. अन्य देयताएं	49,602 (9.3)	52,239 (8.9)	6.1	5.3
आस्तियां				
1. नकद और बैंक में जमा शेष	23,409 (4.4)	26,973 (4.6)	-8.7	15.2
2. निवेश	1,86,745 (34.8)	2,11,380 (35.9)	10.1	13.2
3. ऋण और अग्रिम	2,79,272 (52.1)	3,04,990 (51.8)	5.4	9.2
4. संचित हानि	6,721 (1.3)	7,046 (1.2)	9.5	4.8
5. अन्य आस्तियां	39,830 (7.4)	38,525 (6.5)	13.1	-3.3
कुल देयताएं/ आस्तियां	**5,35,977 (100.0)**	**5,88,914 (100.0)**	**6.9**	**9.9**

टिप्पणियां: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल देयताएं/ आस्तियों के अनुपात को दर्शाते हैं (प्रतिशत में)।
2. वर्ष-दर-वर्ष प्रतिशत घट-बढ़ थोड़ी भिन्न हो सकती है क्योंकि निरपेक्ष संख्याओं का ₹ 1 करोड़ में पूर्णांकन कर दिया गया है।
3. पूर्णांकन के कारण कुल जोड़, घटकों के जोड़ से भिन्न हो सकता है।
4. वर्ष 2019-20 के दौरान, केरल की 13 डीसीसीबी (मल्लापुरम डीसीसीबी को छोड़कर) का केरल एसटीसीबी में समामेलन कर दिया गया। पिछले वर्ष के एसटीसीबी के योग में 13 डीसीसीबी के डेटा को जोड़ दिया गया है ताकि तुलना और वृद्धि दर की गणना की जा सके।

स्रोत: नाबार्ड।

सारणी V.19: जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों का वित्तीय निष्पादन

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	के दौरान		घट बढ़ प्रतिशत	
	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21
1	2	3	4	5
ए: आय (i+ii)	**38,398 (100.0)**	**39,982 (100.0)**	**7.3**	**4.1**
i. ब्याज से होनेवाली आय	36,473 (95)	38,089 (95.3)	7.3	4.4
ii. अन्य आय	1,924 (5)	1,893 (4.7)	8.0	-1.6
बी: व्यय (i+ii+iii)	**37,552 (100.0)**	**38,560 (100.0)**	**6.9**	**2.7**
i. व्ययगत ब्याज	24,830 (66.1)	25,480 (66.1)	7.9	2.6
ii. प्रावधान और आकस्मिक निधियां	3,886 (10.3)	3,720 (9.6)	8.0	-4.3
iii. परिचालनगत व्यय	8,836 (23.5)	9,361 (24.3)	3.9	5.9
जिसमें से: वेतन बिल	5,663 (15.1)	5,864 (15.2)	5.4	3.6
सी: लाभ				
i. परिचालनगत लाभ	4,229	4,723	11.8	11.7
ii. निवल लाभ	846	1,422	28.4	68.1

टिप्पणियां: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल आय/ व्यय के अनुपात को दर्शाते हैं (प्रतिशत में)।
2. वर्ष –दर-वर्ष प्रतिशत घट-बढ़ थोड़ी भिन्न हो सकती है क्योंकि निरपेक्ष संख्याओं का ₹ 1 करोड़ में पूर्णांकन कर दिया गया है।
3. पूर्णांकन के कारण कुल जोड़, घटकों के जोड़ से भिन्न हो सकता है।
4. वर्ष 2019-20 के दौरान, केरल की 13 डीसीसीबी (मल्लापुरम डीसीसीबी को छोड़कर) का केरल एसटीसीबी में समामेलन कर दिया गया। पिछले वर्ष के एसटीसीबी के योग में 13 डीसीसीबी के डेटा को जोड़ दिया गया है ताकि तुलना और वृद्धि दर की गणना की जा सके।

स्रोत: नाबार्ड।

V.46 सभी क्षेत्रों में लाभ कमाने वाली संस्थाओं की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई। अखिल भारतीय स्तर पर निवल लाभ में दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों के डीसीसीबी की हिस्सेदारी अत्यधिक रही। पश्चिमी क्षेत्र में वर्ष 2020-21 के दौरान लाभ में तेजी का मुख्य योगदानकर्ता महाराष्ट्र रहा, जबकि दक्षिणी क्षेत्र में आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा योगदान रहा (परिशिष्ट सारणी V.4)।

आस्ति गुणवत्ता

V.47 वर्ष 2016-17 से डीसीसीबी के आस्ति गुणवत्ता में गिरावट आने लगी, जब कई राज्यों ने कृषि ऋण माफी योजना की घोषणा की। वर्ष 2020-21 में, अवमानक आस्तियों में गिरावट और संदिग्ध आस्तियों में कमी के कारण आस्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ। संयोग से, वर्ष 2016-17 के बाद से मांग के अनुपात में उनकी वसूली अपने उच्चतम स्तर पर रही। आस्ति गुणवत्ता और वसूली अनुपात में सुधार में उत्तरी क्षेत्र को छोड़कर सभी क्षेत्रों ने अपना योगदान दिया। दक्षिणी क्षेत्र में सबसे कम एनपीए अनुपात होने के साथ-साथ उच्चतम वसूली अनुपात भी है (सारणी V.20 और परिशिष्ट सारणी V.4)।

4.1.3 प्राथमिक कृषि ऋण समितियां

V.48 प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (पीएसीएस) अल्पकालिक ग्रामीण सहकारी संरचना में जमीनी स्तर की संस्थाएं हैं। ऐतिहासिक रूप से, समितियां विशेषकर सीमांत

सारणी V.20: जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के सुदृढ़ता संकेतक

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	मार्च के अंत की स्थिति		घट बढ़ प्रतिशत	
	2020	2021	2019-20	2020-21
1	2	3	4	5
ए. कुल एनपीए (i+ii+iii)	**35,298**	**34,761**	**10.3**	**-1.5**
i. अवमानक	15,885	13,940	1.6	-12.2
	(45)	(40.1)		
ii. संदिग्ध	16,990	18,367	22.1	8.1
	(48.1)	(52.8)		
iii. हानि	2,423	2,455	-0.6	1.3
	(6.9)	(7.1)		
बी. ऋण की तुलना में एनपीए अनुपात (%)	**12.6**	**11.4**	-	-
सी. मांग-वसूली अनुपात (%)	**70.2**	**74.9**	-	-

टिप्पणियां: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल देयताएं/ आस्तियों के अनुपात को दर्शाते हैं (प्रतिशत में)।
2. वर्ष –दर-वर्ष प्रतिशत घट-बढ़ थोड़ी भिन्न हो सकती है क्योंकि निरपेक्ष संख्याओं का ₹ 1 करोड़ में पूर्णांकन कर दिया गया है।
3. पूर्णांकन के कारण कुल जोड़, घटकों के जोड़ से भिन्न हो सकता है।
4. वर्ष 2019-20 के दौरान, केरल की 13 डीसीसीबी (मल्लापुरम डीसीसीबी को छोड़कर) का केरल एसटीसीबी में समामेलन कर दिया गया। पिछले वर्ष के एसटीसीबी के योग में 13 डीसीसीबी के डेटा को जोड़ दिया गया है ताकि तुलना और वृद्धि दर की गणना की जा सके।
5. वसूली की स्थिति समान वित्तीय वर्ष की 30 जून की स्थिति के अनुसार है।

स्रोत: नाबार्ड।

किसानों को अल्पकालिक और मध्यम अवधि के कृषि ऋण प्रदान करने के लिए उधार और जमा दोनों के माध्यम से संसाधन जुटाती हैं। वे अपने सदस्यों के लिए कृषि निवेश संबंधी वस्तुओं की आपूर्ति, उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण और उपज के विपणन सहित अन्य गतिविधियों से संबंधित भी काम करती हैं।

V.49 मार्च 2021 की समाप्ति तक, पीएसीएस ने 13.7 करोड़ सदस्यों और 5.4 करोड़ उधारकर्ताओं को सेवा प्रदान की। पश्चिमी क्षेत्र (मुख्य रूप से महाराष्ट्र) में इसकी उपस्थिति प्रमुख रूप से है, इसके बाद पूर्वी क्षेत्र का स्थान है। सदस्य उधारकर्ता अनुपात - पीएसीएस का एक ऋण-संकेंद्रण मापक, वर्ष 2016-17 में 39.6 प्रतिशत से उत्तरोत्तर कम होकर वर्ष 2019-20 में 38 प्रतिशत हो गया। हालांकि, वर्ष 2020-2021 के दौरान, यह अनुपात बढ़कर 39.1 प्रतिशत हो गया, जो मुख्य रूप से कुल सदस्यता में गिरावट और कुल उधारकर्ताओं[9] की संख्या में वृद्धि को दर्शाता है। ग्रामीण कारीगरों और 'अन्य तथा सीमांत किसानों' की सदस्यता में वृद्धि हुई (परिशिष्ट सारणी V.7)।

V.50 एसटीसीबी और डीसीसीबी के एनपीए अनुपात के संदर्भ में मापी गई आस्ति की गुणवत्ता, ऐतिहासिक रूप से, पीएसीएस से बेहतर रही है। इसके अतिरिक्त, उनका वसूली अनुपात भी लगातार दो वर्षों से अपने निम्नतम स्तर पर बना हुआ है (सारणी V.13 और चार्ट V.18)।

चार्ट V.18: अल्पावधिक सहकारी संस्थाओं की आस्ति गुणवत्ता: एक तुलना

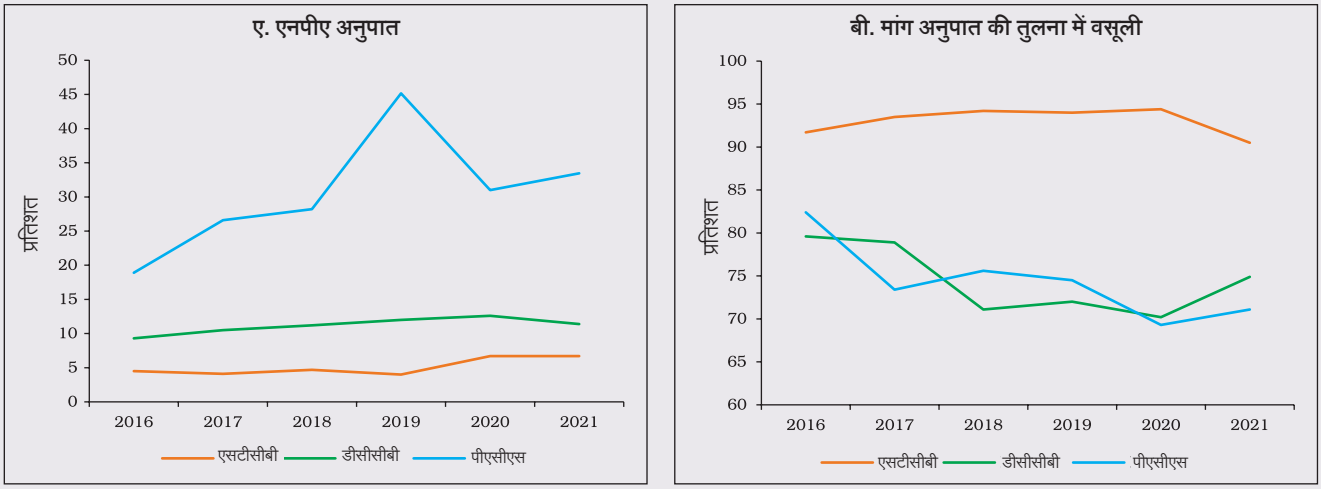

स्रोत: नाबार्ड और एनएएफएससीओबी।

[9] नाबार्ड की वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 - https://www.nabard.org/nabard-annual-report-2021-22.aspx पर उपलब्ध है।

V.51 वर्ष 2020-21 के दौरान पीएसीएस के कुल संसाधनों में गिरावट आई। सरकारी योगदान में महत्वपूर्ण वृद्धि के बावजूद, वर्ष 2020-21 में स्वामित्व वाली निधियों में कमी आई, जो सदस्यता आधार में गिरावट को दर्शाती है, और प्रदत्त पूंजी में नकारात्मक वृद्धि का कारण बनी (परिशिष्ट सारणी V.5)। अपने अधिदेश के अनुरूप, पीएसीएस मध्यम अवधि के ऋणों की तुलना में आनुपातिक रूप से अधिक अल्पकालिक ऋण प्रदान करते हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, लघु और मध्यम अवधि के दोनों ऋणों में लगभग 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई, इस प्रकार कुल में अल्पावधि ऋणों की हिस्सेदारी 88 प्रतिशत बनी रही।

V.52 पीएसीएस का व्यापार मॉडल काफी हद तक कृषि को ऋण देने की ओर अग्रसर हुआ है। मार्च 2021 की समाप्ति तक कुल उधार में इसकी हिस्सेदारी 80 प्रतिशत के उच्च स्तर पर थी। हालांकि, वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के आधार पर, इनका कृषि ऋण, पिछले वर्ष के 6.8 प्रतिशत की तुलना में घटकर 3.9 प्रतिशत रह गया।

V.53 वर्ष के दौरान आधे से ज्यादा पीएसीएस लाभ में थे जिन्होंने नुकसान के बावजूद आधे से अधिक पीएसीएस ने लाभ अर्जित किया। क्षेत्र-वार संकलन से पता चलता है कि 70 प्रतिशत से अधिक समितियों के लाभ में होने से केवल उत्तरी क्षेत्र की समितियां लाभ में थीं, जिसमें मुख्य रूप से हरियाणा और राजस्थान का योगदान था। दक्षिणी क्षेत्र में नुकसान सबसे अधिक था, जिसमें मुख्य रूप से केरल और तमिलनाडु का योगदान था (परिशिष्ट सारणी V.6)।

4.2 दीर्घावधिक ग्रामीण सहकारी संस्थाएं

V.54 दीर्घावधिक ग्रामीण सहकारी संस्थाओं की स्थापना कृषि में निवेश हेतु निधि उपलब्ध करवाने- जिसमें भूमि विकास, कृषि मशीनीकरण और लघु सिंचाई - ग्रामीण उद्योग और आवास शामिल हैं, के लिए की गई थी। इसकी संरचना में राज्य स्तर पर कार्यरत 13 राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (एससीएआरडीबी) तथा जिला/ब्लॉक स्तर पर संचालित 603 प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (पीसीएआरडीबी) शामिल हैं। दीर्घकालिक ग्रामीण सहकारी समितियों की संरचना राज्यों में भिन्न-भिन्न होती हैं। जम्मू और कश्मीर, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, गुजरात और पुडुचेरी जैसे राज्य एकात्मक संरचना का पालन करते हैं, अर्थात एससीएआरडीबी अपनी स्वयं की शाखाओं के माध्यम से संचालित होते हैं जिनमें कोई अलग पीसीएआरडीबी नहीं होता है। दूसरी ओर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्य एक संघीय ढांचे का पालन करते हैं जिसमें एससीएआरडीबी, पीसीएआरडीबी के माध्यम से उधार देते हैं। दो राज्यों में यथा हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल, एससीएआरडीबी, पीसीएआरडीबी के साथ-साथ अपनी स्वयं की शाखाओं के माध्यम से कार्य करती हैं।

V.55 एससीएआरडीबी और पीसीएआरडीबी का व्यवसाय मॉडल उधार पर बहुत अधिक निर्भर करता है; उक्त में से पूर्व वाले प्रत्यक्ष उधार देने के लिए पीसीएआरडीबी के साथ-साथ उधार देने के लिए नाबार्ड जैसे संस्थानों से उधार लेते हैं। पीसीएआरडीबी की वित्तीय स्थिति एससीएआरडीबी की तुलना में अधिक नाजुक है क्योंकि उनके तुलन पत्र में संचित हानि का भाग ज्यादा है (चार्ट V.19)।

4.2.1 राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (एससीएआरडीबी)

V.56 794 शाखाओं के साथ एससीएआरडीबी 13 राज्यों में काम कर रही हैं, जिनमें से सबसे अधिक शाखाएँ उत्तर प्रदेश में हैं। एससीएआरडीबी की समेकित तुलन-पत्र में लगातार तीन वर्षों तक कमी देखने के बाद, वर्ष 2020-21 में मामूली रूप से बढ़ोतरी हुई। यह बढ़ोतरी देनदारी पक्ष में जमाराशि द्वारा और आस्ति पक्ष में ऋणों और अग्रिमों में निरंतर तेजी द्वारा समर्थित थी (परिशिष्ट V.8)।

V.57 हालांकि आय - ब्याज के साथ-साथ ब्याजेतर - और व्यय दोनों पिछले वर्ष की तुलना में कम हुए हैं, आय में गिरावट, व्यय की तुलना में अधिक थी, जिससे लाभप्रदता में गिरावट आई (परिशिष्ट सारणी V.9)।

चार्ट V.19: दीर्घकालिक ग्रामीण सहकारी संस्थाओं की देयताएं और आस्तियां : एक तुलना
(मार्च 2021 के अंत में)

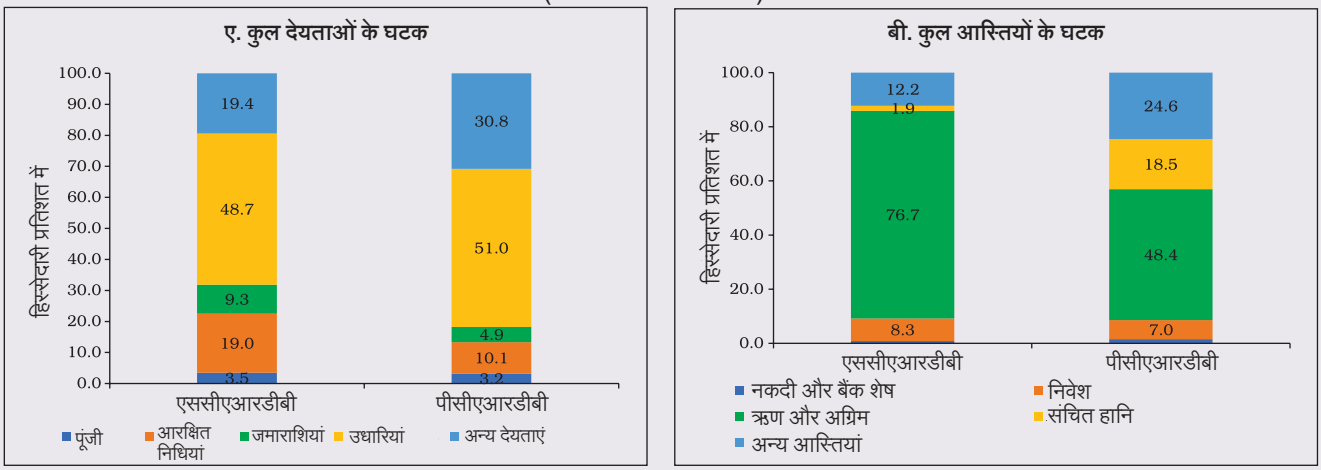

स्रोत: नाबार्ड।

V.58 अवमानक आस्तियों में संकुचन के कारण वर्ष 2020-21 में एससीएआरडीबी के एनपीए में कम वृद्धि देखी गई। वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 में मांग-वसूली अनुपात में सुधार हुआ, जिसमें मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और केरल का योगदान रहा (परिशिष्ट सारणी V.10 और V.11)।

4.2.2 प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (पीसीएआरडीबी)

V.59 आस्ति पक्ष में ऋण एवं अग्रिम के साथ-साथ देयताएं पक्ष में उधार में संकुचन के कारण वर्ष 2020-21 के दौरान पीसीएआरडीबी की समेकित तुलन-पत्र में कमी आई (परिशिष्ट तालिका V.12)।

V.60 व्यय से ज्यादा आय में वृद्धि होने से पीसीएआरडीबी के परिचालन लाभ में तेजी आई। हालांकि, उनकी प्रावधान संबंधी आवश्यकताएं अधिक बनी रहीं तथा निवल घाटे की ऐतिहासिक प्रवृत्ति जारी रही (परिशिष्ट सारणी V.13)। सकारात्मक पक्ष यह है कि अवमानक आस्तियों में गिरावट के कारण वर्ष 2020-21 में एनपीए अभिवृद्धि धीमी हुई है (परिशिष्ट सारणी V.14)। हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल को छोड़कर, सभी राज्यों के लिए मांग अनुपात के सुधार में कमी आई (परिशिष्ट तालिका V.15)।

5. समग्र मूल्यांकन

V.61 वर्ष 2021-22 के दौरान, यूसीबी का प्रदर्शन सभी मापदंडों - पूंजी बफर, आस्ति गुणवत्ता और लाभप्रदता - पर सुधरा। एक बड़े दबावग्रस्त यूसीबी के समामेलन ने इस क्षेत्र में प्रदर्शन को बढ़ाने में मदद की, हालांकि, अन्य दबावग्रस्त और कमजोर यूसीबी की स्वयंसमर्थता सुनिश्चित करने के लिए ध्यान से निगरानी की आवश्यकता है। हालांकि, ग्रामीण सहकारी समितियों के कुछ क्षेत्रों के कार्य-निष्पादन में सुधार करने की जरूरत है। रिज़र्व बैंक द्वारा हाल ही में शुरू किए गए विधिक और विनियामकीय उपायों से इस क्षेत्र की वित्तीय स्थिति मजबूत होने की संभावना है जिससे वे वित्तीय समावेश के कड़ी के रूप में अपनी भूमिका अधिक प्रभावी ढंग से निभा सकें।